वर्ष 12 • अंक 271 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 1 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 2

बहुराष्ट्रीय व देसी दवा कंपनियों ने किया बेहतर प्रदर्शन

रजनीश कुमार ▶▶ पृष्ठ 3

दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए एसबीआई बनाएगा कोष

डॉलर रु. 71.40 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 80.10 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39083 ▲ 261 रुपये | सेंसेक्स 41253.70 ▼ 304.30 | निफ्टी 12168.50 ▼ 87.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 12246.30 ▲ 77.80 | ब्रेंट क्रूड 66.40 डॉलर ▼ 0.70 डॉलर

प्रिय पाठकों को

नव वर्ष की शुभ कामनाएं

एक नज़र

प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन लगातार तीसरे महीने घटा

अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन नवंबर में लगातार तीसरे महीने 1.5 फीसदी घटा है। इसकी वजह यह है कि रिफाइनरी उत्पाद और बिजली जैसे अहम क्षेत्रों में वृद्धि धीमी है या गिर रही है। इन क्षेत्रों के उत्पादन में अक्टूबर में रिकॉर्ड 5.8 फीसदी और सितंबर में 5.2 फीसदी गिरावट आई थी। इसके नतीजतन चालू वित्त वर्ष 2020 में नवंबर तक कोर सेक्टरों की समग्र वृद्धि शून्य रही है, जो पिछले साल 5.1 फीसदी थी। पृष्ठ 4

आज से रेल से सफर करना हुआ महंगा

नए साल में रेलवे से सफर करना महंगा हो गया है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार किराए में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि रेलवे ने उप-नगरीय रेल सेवाओं के लिए किराया नहीं बढ़ाया है। साधारण गैर-वातानुकूलित, गैर-उप नगरीय रेल किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा हुआ है। इसी तरह, मेल/एक्सप्रेस गैर-वातानुकूलित दर्जे का किराया 2 पैसे और वातनुकूलित दर्जे का किराया 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियां भी इनमें शामिल हैं।

लघु बचत योजनाओं की दरें अपरिवर्तित

सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत पत्र पर सालाना ब्याज दर 7.9 प्रतिशत बरकरार रखी गई है, जबकि किसान विकास पत्र पर 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा और यह 113 महीने में परिपक्व होगा। लघु बचत योजनाओं पर तिमाही आधार पर ब्याज दरें तय होती हैं।

जापान से भागकर लेबनान पहुंचे कार्लोस गोन

वित्तीय आरोपों का सामना कर रहे जापानी कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गोन जापान से लेबनान भाग गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह कानून से नहीं भाग रहे हैं लेकिन उन्होंने अन्याय और राजनीतिक प्रताड़ना से बचने के लिए जापान छोड़ा है। टोक्यो की एक अदालत ने उन्हें हाल में ही जमानत दी थी लेकिन उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के जरिये जारी एक बयान में अपने लेबनान में होने की बात कही लेकिन यह नहीं बताया कि वह जापान से कैसे भागे।

त्यापार गोष्ठी

नए साल से आर्थिक एवं कारोबारी उम्मीदें ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या ढांचागत क्षेत्र पर जोर देने से देश की अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अगले वित्त वर्ष देश की आर्थिक विकास दर में आएगी तेजी	
हां	25.00%
नहीं	75.00%

SOLITAIRE PRICE INDEX

1st January, 2020		
4,214*	0.49%↓ Over last Month	0.26%↑ Over last Year

Nationwide Standard & Transparent Pricing since 2006. Published on the 1st of every month.

DIVINE® SOLITAIRES

*This is an average of Divine Solitaires Price List

Call: 022-66264800 | www.divinesolitaires.com

ढांचागत परियोजनाओं पर जोर

वित्त मंत्री ने 102 लाख करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी योजना की घोषणा की

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 102 लाख करोड़ रुपये महत्त्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) रिपोर्ट जारी करते हुए आज कहा कि 23 क्षेत्रों और 18 राज्यों में उन परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है जिन पर अगले पांच साल के दौरान अमल किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि इन परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारें 39-39 फीसदी राशि देंगे जबकि निजी क्षेत्र 22 फीसदी निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 2024-25 तक निजी क्षेत्र की भागीदारी 30 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद कर रही है। वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में इसमें तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं और शामिल हो सकती हैं। इस तरह इस योजना पर कुल राशि 105 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती हैं।

इस योजना में केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र और सरकारी कंपनियों की नई-पुरानी परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल के तहत आने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 42.7 लाख करोड़ रुपये (43 फीसदी) लागत की परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, 32.7 लाख करोड़ रुपये (करीब 33 फीसदी) लागत की परियोजनाएं कतार में हैं और 19.1 लाख करोड़ रुपये (करीब 19 फीसदी) लागत की परियोजनाएं पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि देश में अगले पांच साल में बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उससे पहले आम बजट में भी इसका जिक्र था। सीतारमण ने कहा कि आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की अगुआई में गठित एक कार्य बल ने चार महीने के अल्पावधि में 70 संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श करने के बाद 102 लाख करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं की पहचान की। कार्य बल की पहली बैठक सितंबर, 2019 में हुई थी। इसके बाद बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों तथा कंपनियों के साथ कई बैठकें हुई।

इस मौके पर चक्रवर्ती ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र का निवेश देश के मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.8 फीसदी है और सरकार को उम्मीद है कि 2024-25 तक यह आंकड़ा 1.1 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

इस योजना के लिए जिन क्षेत्रों की परियोजनाओं पहचान हुई है उनमें परंपरागत ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा, रेलवे, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, उड्डयन, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र को जाने की उम्मीद है। इसमें बिजली, अक्षय ऊर्जा, तेल और गैस शामिल है। करीब 24 लाख करोड़ रुपये की परियोजना बिजली क्षेत्र की हैं। इसी तरह सड़क निर्माण क्षेत्र की 20 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं और करीब 14 लाख करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती को देखते हुए इन परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना आसान नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (दाएं) वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती के साथ नई दिल्ली में मंगलवार को नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन की शुरुआत के अवसर पर । *फोटोः दलीप कुमार*

अर्थव्यवस्था को मजबूती

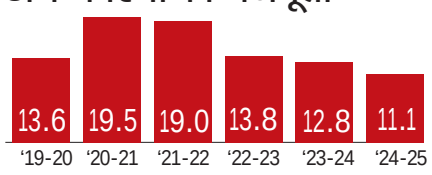

2019-20 के अनुमानित आंकड़े, अन्य वर्षों के संभावित आंकड़ों तालिका में बिजली क्षेत्र शामिल नहीं

39-39 % परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य दोनों करेंगे

22% का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र करेगा

42% परियोजना क्रियान्वयन के अधीन, 31 प्रतिशत संकल्पना के स्तर पर

नए साल में सुधार के कम आसार

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

भारतीय कंपनियों के ज्यादातर मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) को नए साल में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं हैं। उन्हें लगता है कि 2019 में हिचकोले खाने के बाद नए साल में भी अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता रहेगी। सीईओ के अनुसार दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के मोर्चे पर तनातनी से हालात और खराब रह सकते हैं और इससे भारत में मांग कमजोर रह सकती है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने देश भर में दिसंबर में 50 सीईओ से बात की। इस सर्वेक्षण में 52 प्रतिशत सीईओ ने नए साल में अर्थव्यवस्था और फिसलने की आशंका जताई है। 6 प्रतिशत लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, जबकि शेष 42 प्रतिशत लोगों का मानना था कि बुरे हालात अब बीते दिनों की बात हो चुकी है।

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर जो हालात दिख रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि सुधार आने में थोड़ा और समय लग सकता है। त्योहारी मौसम के कारण इस तिमाही से खासी उम्मीदें थीं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हालात में निरंतर सुधार की जरूरत है।'

तीसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर कम होकर मात्र 4.5 प्रतिशत रह गई। दिसंबर तिमाही में सीईओ ने जीडीपी दर कम होकर 4 प्रतिशत से नीचे रहने की आशंका जताई है। करीब 56 प्रतिशत सीईओ का मानना है कि अर्थव्यवस्था में शिथिलता चिंता का मुख्य कारण है। सीईओ ने कहा कि खुदरा उपभोक्ता ने खर्च करना बंद कर दिया है और इससे अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित हो रही है। उनके अनुसार वाहन एवं उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री के कमजोर आंकड़े इस बात केपुख्ता सबूत हैं। एक बड़ी उपभोक्ता के सीईओ ने कहा, 'छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बहुत अधिक नहीं देखी जा रही है। बड़े शहरों में जरूर गतिविधियां दिखी हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर त्योहारी मौसम तक ही सिमट कर रह गई हैं।'

हालांकि 62 प्रतिशत सीईओ को लगता है कि 2020 में मांग में मौजूदा स्तर से तेजी आएगी। उनके अनुसार अगर आयकर दर में कमी की गई तो इससे देश में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीईओ के अनुसार आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की घोषणाएं स्थिति में सुधार ला सकती हैं। एक बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी के सीईओ ने कहा, 'व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दर तर्कसंगत बनाने और कंपनियों में कर अधिकारियों का खौफ कम करने जैसे उपाय प्रावधान बजट में होने चाहिए। बजट में निवेश में दोबारा तेजी लाने के उपायों का भी जिक्र होना चाहिए।' शेष पृष्ठ 12

सीईओ का अनुमान

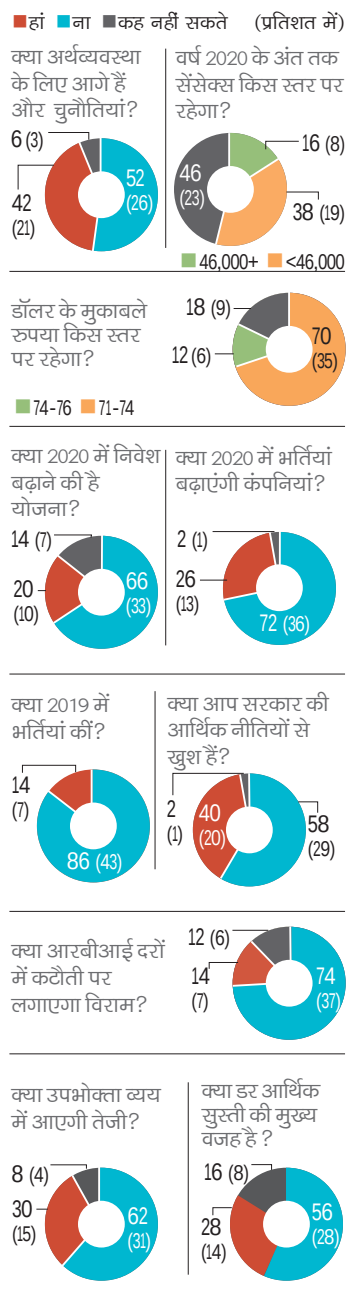

नोटः बिजनेस स्टैंडर्ड ने दिसंबर में देश भर में 50 मुख्य कार्याधिकारियों से बातचीत की। कोष्ठक में वास्तविक आंकड़े दर्शाए गए हैं

चमकेंगे मझोले और छोटे शेयर!

जश कृपलानी एवं सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 31 दिसंबर

- **अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने के बाद नए साल में मझोले एवं छोटे शेयरों में भी आ सकती है तेजी**
- **म्युचुअल फंड प्रबंधकों के अनुसार इन शेयरों में अब और गिरावट की आशंका नहीं**

नए साल में मझोले एवं छोटे शेयर अपना खोया वजूद दोबार हासिल कर सकते हैं। घरेलू म्युचुअल फंड प्रबंधकों के अनुसार 2019 इन शेयरों के लिए नागवार गुजरा, लेकिन नए साल में इनकी परेशानियां कम हो सकती है। फंड प्रबंधकों के सरकारी उपायों के बाद अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने के बाद मझोले एवं छोटे शेयरों में भी मजबूती दिखेगी। आईडीएफसी म्युचुअल फंड में इक्विटी प्रमुख अनूप भास्कर ने कहा,'पिछले दो वर्षों में वृहद बाजारों में अपनी कम भागीदारी के बाद नए साल में ये शेयर कारोबारी संभावनाओं के लिहाज से आकर्षक साबित हो सकते हैं।

मझोले एवं छोटे शेयरों का मूल्यांकन अब वाजिब स्तरों तक आ गया है, इसलिए अब इनमें और अधिक गिरावट की गुंजाइश नहीं है।' कोटक म्युचुअल फंड में इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधक पंकज टिबरेवाल ने कहा कि निफ्टी और मझोले एवं छोटे शेयरों में अंतर ऐतिहासिल स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि इससे और अधिक गिरावट के बारे में कुछ कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि वृहद सूचकांक इन स्तरों पर पहुंचने के बाद 28-24 महीने तक उम्दा प्रदर्शन करते हैं।

2019 में बीएसई मिड-कैप सितंबर में कॉर्पोरेट कर में कमी से पहले तक 15 प्रतिशत फिसल चुका था। इसी अवधि के दौरान बीएसई स्मॉल-कैप में 17 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई। 2018 में बीएसई मिड-कैप 13.4 प्रतिशत तक नीचे लुढ़का था, जबकि बीएसई स्मॉल-कैप में 24 प्रतिशत गिरावट आई थी।

फंड प्रबंधकों का कहना है कि जब कभी भी छोटे शेयरों के कीमत एवं आय का अनुपात कम होकर निफ्टी का 40-45 प्रतिशत तक रह गया है तो इससे आगे गिरावट नहीं देखी गई है। इस समय निफ्टी एक साल के प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल के करीब 14.5 गुना स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल-कैप के बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी निफ्टी के बाजार मूल्यांकन का 5.3 प्रतिशत है। यह पिछले छह वर्षों में दर्ज सबसे निचले सतरों के करीब है।

भास्कर ने कहा, 'इससे पहले भी इन स्तरों के निकट मझोले एवं छोटे शेयरों में गिरावट थमती देखी गई है।' बाजार पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि कमजोर उत्साह के बीच अच्छी गुणवत्ता वाले मझोले एवं छोटे शेयर भी बिकवाली की चपेट में आए हैं।

15 फीसदी ऊपर राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के पहले आठ महीने में लक्ष्य का 114.8 फीसदी पहुंच गया। महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के अंत में सरकार के राजस्व और खर्च में अंतर 8.07 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपये अधिक है। सकल कर राजस्व में लगातार कमी और खर्च में निरंतर बढ़ोतरी से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा है जिससे वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही राजकोषीय घाटा लक्ष्य से पार चला गया है।

अप्रैल से नवंबर के दौरान कंपनी कर संग्रह में एक फीसदी की कमी आई जबकि सड़कों पर बजटीय पूंजीगत खर्च बढ़ने से व्यय का बोझ बढ़ा है। किसानों के लिए आय समर्थन सहायता और खाद्य सब्सिडी से भी राजस्व खर्च पर मार पड़ी है। *बीएस*

उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना

सोने की कीमतों में लगातार सात दिन की तेजी के साथ ही ये कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को सोने के हाजिर कारोबार में कीमतों में 0.7 प्रतिशत की तेजी आई और ये सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिसके कारण ग्राहक फिलहाल नए ऑर्डर देने से दूरी बना रहे हैं।

पिछले 10 दिनों के दौरान मुंबई के प्रसिद्ध जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में तीन प्रतिशत तथा चांदी की कीमतों में छह प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोना कारोबार 39,083 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 46,665 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बंद हुआ। तीन प्रतिशत जीएसटी को जोड़ा जाए तो ग्राहकों को 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 40,000 रुपये से अधिक राशि खर्च करनी होगी। पृष्ठ 6

हजारों जौहरियों को कर मांग का नोटिस

राजेश भयानी
मुंबई, 31 दिसंबर

आय कर विभाग ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर नकदी जमा कराने वाले देशभर के हजारों जौहरियों को कर मांग का नोटिस भेजा है। इनमें से अधिकांश नोटिस आज भेजे गए क्योंकि यह वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नोटिस भेजने का आखिरी दिन था। नोटबंदी की घोषणा नवंबर 2016 में की गई थी और 2016-17 में ही यह नकदी जमा कराई गई थी।

इससे उद्योग में नई चिंता व्याप्त हो गई है कि सुस्ती का सामना कर रहे जौहरी कर मांग का भुगतान कर पाएंगे या नहीं। पिछले छह महीनों से उनका कारोबार मंदा पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से अधिकांश जौहरियों को अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। नैशनल बुलियन ऐंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, 'आय कर विभाग की तरफ से जौहरियों को वसूली नोटिस की खबरों के मद्देनजर हमने सभी आभूषण निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को कोई भी नया माल देने से पहले जौहरियों का सही ढंग से केवाईसी करने की सलाह दी है।'

सूत्रों के मुताबिक केवल मुंबई में ही कर विभाग ने करीब 500 जौहरियों को कर मांग का नोटिस भेजा है। नई दिल्ली में यह संख्या और ज्यादा है। देश में तीन लाख से अधिक जौहरी हैं और नोटबंदी के बाद इनमें से कई सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए पुराने नोटों को लेने में बेहद सक्रिय थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी तो व्यापारियों को उस दिन रात 12 बजे तक नकद बिक्री पर पुराने नोट लेने की अनुमति दी गई थी। अलबत्ता, कई जौहरी उसके बाद भी बहुत दिनों तक प्रतिबंधित नोटों को लेते रहे। उन्होंने 30 से 40 फीसदी महंगे दामों पर सोना बेचा और जमकर मुनाफा कमाया। जौहरियों पर आय कर विभाग के नोटिस से दोहरी मार पड़ी है। एक सूत्र ने कहा कि कर मांग में आय कर, जुर्माना और आज तक का ब्याज शामिल है जो उनके द्वारा जमा की गई नकदी के बराबर ही है। इसके अलावा जो सोना बेचा गया उसका मूल्य भी जौहरियों के लिए नुकसानदायक होगा। इस बात की जानकारी नहीं है कि पूरे देश में कुल कितने जौहरियों को कर मांग का नोटिस जारी किया गया है और वसूली की राशि कितनी है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि कई हजार जौहरियों को कर मांग का नोटिस मिला है और जुर्माने तथा ब्याज के साथ वसूली की राशि बहुत अधिक है। उद्योग के एक दिग्गज ने कहा कि नोटबंदी के बाद ऐसी खबरें थीं कि जयपुर और गुजरात में कुछ जौहरियों में से प्रत्येक ने 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराए थे। जिन जौहरियों को यह नोटिस मिला है उन्हें अपील दायर करने से पहले कर मांग की कम से कम 20 फीसदी राशि जमा करनी होगी।

कई जौहरियों को बंद करना पड़ सकता है कारोबार

- **नोटबंदी के बाद जमा कराई थी मोटी नकदी**
- **कर मांग में कर, जुर्माना और ब्याज भी शामिल**
- **वसूली की राशि जमा राशि के लगभग बराबर**

खबरों में रहे स्टॉक

अदाणी ग्रीन एनर्जी

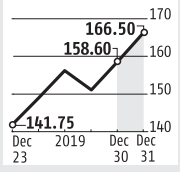

300 फीसदी तेजी के साथ 2019 में सबसे ज्यादा कीमत सृजन वाली फर्म

₹ 158.60 पिछला बंद भाव
₹ 166.50 आज का बंद भाव
▲ 4.98 %

केयर रेटिंग्स

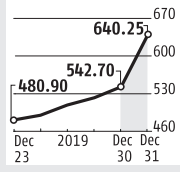

ए समूह में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर

₹ 542.70 पिछला बंद भाव
₹ 640.25 आज का बंद भाव
▲ 17.97 %

एचईजी

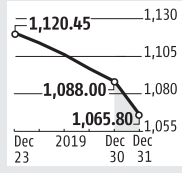

दिसंबर तिमाही में एलआईसी ने 1.52 फीसदी घटाई हिस्सेदारी

₹ 1,088.00 पिछला बंद भाव
₹ 1,065.80 आज का बंद भाव
▼ 2.04 %

येस बैंक

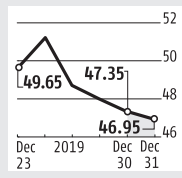

2019 में निफ्टी-50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर, 74 फीसदी फिसला

₹ 47.35 पिछला बंद भाव
₹ 46.95 आज का बंद भाव
▼ 1.00 %

एनटीपीसी

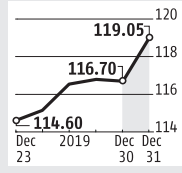

स्थापित क्षमता में जुड़ी 800 मेगावॉट की दरलीपाली परियोजना

₹ 116.70 पिछला बंद भाव
₹ 119.05 आज का बंद भाव
▲ 2.01 %

संक्षेप में

प्रदीप माथुर होंगे गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

घोटाले से जूझ रही सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने प्रदीप माथुर को कंपनी के अतिरिक्त एवं गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीजी पावर ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि माथुर की नियुक्ति पर अगली सालाना आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी ली जाएगी। उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए होगी। इसमें कहा गया सीजी पावर के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर प्रदीप माथुर को 30 दिसंबर 2019 से कंपनी का अतिरिक्त और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। माथुर को करीब 37 साल का अनुभव है और वह पूर्व में टप्परवेयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में काम रहे थे। वह वर्तमान में लेमन ट्री होटल्स और उसकी कुछ अनुषंगी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। सीजी पावर ने अगस्त में कहा था कि उसके बोर्ड द्वारा की गई जांच में कंपनी के संचालन और वित्तीय लेनदेन में खामियां दिखी थीं। *भाषा*

अमित तलगेरी बने ऐक्सिस बैंक के जोखिम अधिकारी

एक्सिस बैंक ने अमित तलगेरी को मंगलवार को अपना मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया। नियुक्ति एक जनवरी 2020 से लागू होगी। वह तीन साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह सिरिल आनंद की जगह लेंगे। एक्सिस बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा, ' बैंक के सीआरओ सिरिल आनंद 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।' बैंक ने नवीन ताहिलयानी को समूह कार्यकारी (बैंकिंग परिचालन एवं परिवर्तन) बनाया गया है। उनकी नियुक्ति छह जनवरी से प्रभावी होगी। *भाषा*

हीरो मोटोकॉर्प ने एचएफ डीलक्स बीएस-6 पेश की

हीरो मोटोकॉर्प ने मंगलवार को 100 सीसी क्षमता वाली एचएफडीलक्स मोटरसाइकिल का बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाला संस्करण उतारा। इसकी कीमत 55,925 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एचएफडीलक्स बीएस-6 के सेल्फस्टार्ट एवं एलॉय व्हील संस्करण की शोरूम पर कीमत 55,925 रुपये तथा सेल्फस्टार्ट अलॉय आई 3एस संस्करण की कीमत 57,250 रुपये रखी गयी है। इससे पहले कंपनी बीएस-6 उत्सर्जन मानक की स्पेन्डर आईस्मार्ट पेश कर चुकी है। *भाषा*

'सस्ती कीमतों से परहेज करें एयरलाइन'

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

सस्ते टिकटों से पड़ रहा एयरलाइन पर दबाव

- दिल्ली-मुंबई क्षेत्र हवाई क्षेत्र में कीमतें पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ी हैं
- नागरिक उड्डयन मंत्री ने विमानन उद्योग को दूरसंचार क्षेत्र से सबक लेने की नसीहत दी
- दूरसंचार कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से दबाव का सामना करना पड़ा है

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्योग में लगातार नुकसान के लिए एयरलाइनों द्वारा सस्ती कीमतों से ग्राहकों को लुभाने की होड़ को जिम्मेदार बताया। हालांकि मंत्री ने मौजूदा समय में किसी तरह के नियामकीय दखल से इनकार किया और कहा कि जब भी सस्ते मूल्य निर्धारण के मामले दिखते हैं, एयरलाइनों को नियमित तौर पर चेताया जाता है।

मौजूदा नियमों के तहत, एयरलाइनों को विमान यात्रा के किराए के निर्धारण की अपनी प्रक्रिया तैयार करने का विशेषाधिकार है। एयरलाइनों के वाणिज्यिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। पुरी ने दिल्ली-मुंबई क्षेत्र (जहां कीमतें पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ी हैं) का उदाहरण देते हुए कहा, 'हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें एयरलाइनें अपने टिकटों का मूल्य निर्धारण उस कीमत पर कर रही हैं जो उनकी परिचालन लागत की तुलना में कम है। ऐसे उपाय अल्पावधि में तो लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन दीर्घावधि में इससे पूरा उद्योग प्रभावित होता है।'

मंत्री ने कहा, 'दिल्ली-मुंबई क्षेत्र पर विमान किराया 10 साल पहले के किराये के समान है। यह निश्चित तौर पर तर्कसंगत मूल्य निर्धारण नहीं है।'

स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह ने पिछले महीने इसी तरह का तर्क पेश करते हुए कहा था कि प्रतिस्सपर्धी दबाव कम किराया व्यवस्था के लिए बाध्य कर रहा है जिससे भारत के विमानन क्षेत्र को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत की दूरसंचार कंपनियों के साथ तुलना करते हुए सिंह ने कहा, 'हमें दूरसंचार क्षेत्र से सबक लेना चाहिए। हमें तत्काल कदम उठाने और सस्ती कीमत पर टिकट बिक्री बंद करने की जरूरत है।'

भारत की दूरसंचार कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से दबाव का सामना करना पड़ा है। इन कंपनियों को अपनी दरें घटाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जिससे भारती एयरटेल और वोडाफोन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उद्योग का मानना है कि वोडाफोन इंडिया अपनी अनिश्चित वित्तीय स्थिति की वजह से परिचालन बंद कर सकती है। विमामन परामर्श फर्म सीएपीए के अनुसार, भारतीय एयरलाइनों को वित्त वर्ष 2019-20 में 60 करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान होने की आशंका है जबकि पूरे वर्ष के संदर्भ में पिछले अनुमान में इस क्षेत्र को 50 करोड़ डॉलर से 70 करोड़ डॉलर का लाभ होने का अंदाजा लगाया गया था।

बीएसई पर सूचीबद्ध भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइनों - इंटरग्लोब एविएशन द्वारा परिचालन इंडिगो और अजय सिंह के नेतृत्व वाली स्पाइसजेट ने सितंबर तिमाही में भारी नुकसान दर्ज किया। स्पाइसजेट को सितंबर तिमाही में 461.22 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ। उसे पिछले साल 382.72 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था। वहीं इंडिगो को भी सितंबर तिमाही के दौरान उम्मीद से ज्यादा नुकसान हुआ। इंडिगो पर ऊंची मैंटेनेंस और इससे संबंधित अन्य लागत से दबाव पड़ा। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन ने एक साल पहले के 652 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में सितंबर तिमाही में 1,062 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया।

हालांकि पुरी ने कहा कि फिलहाल सरकार सस्ते मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को रोकने के लिए किसी तरह के नियामकीय हस्तक्षेप पर विचार नहीं कर रही है।

नए साल में कम पायलट नियुक्त करेंगी भारतीय एयरलाइन

अनीश फडणीस
मुंबई, 31 दिसंबर

भारतीय एयरलाइनों द्वारा इस साल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम संख्या में पायलटों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। इसकी वजह एयरबस से विमानों की आपूर्ति में विलंब, बोइंग 737 मैक्स को फिर से सेवा में शामिल किए जाने को लेकर अनिश्चितता और जेट एयरवेज से निकले पायलटों के लिए प्रशिक्षण है।

2019 में भारतीय विमानन कंपनियों ने 2,301 पायलटों की नियुक्ति की, जिनमें से कई जेट एयरवेज से शामिल किए गए। जेट एयरवेज ने अप्रैल में अपना परिचालन बंद कर दिया। 2018 और 2017 में एयरलाइनों ने परीक्षाओं के जरिये 1696 और 1221 पायलटों को नियुक्त किया।

> 2019 में भारतीय विमानन कंपनियों ने 2,301 पायलटों की नियुक्ति की, जिनमें से कई जेट एयरवेज से शामिल किए गए

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) अरुण कुमार ने कहा, 'भारतीय विमानन कंपनियों के पास 2020 में एयरबस ए320 और बोइंग 737 विमानों के लिए स्थानीय तौर पर पर्याप्त पायलट होंगे, लेकिन एटीआर-72 और क्यू-400 जैसे छोटे टर्बोप्रॉप विमानों के लिए विदेशी पायलटों पर निर्भरता बरकरार रहेगी।'

डीजीसीए सैन्य छात्रों के साथ साथ भारतीय वायुसेना कर्मियों और अन्य के लिए हर साल 700-800 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करता है। कुमार ने कहा कि फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों को सशक्त बनाया जा रहा है। इस वजह से पायलटों की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है।

पिछले सप्ताह, गोयर ने छुट्टी बिताने के लिए यात्रा करने वाले सैकड़ों लोगों को मायूस किया था, क्योंकि उन दिनों पायलटों के अभाव की वजह से हर दिन लगभग 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। हालांकि गोयर ने कहा कि पायलटों का अभाव नहीं था, और उसने खराब मौसम जैसे अन्य कारकों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। सूत्रों का कहना है कि एयरलाइन अपने पायलटों की टीम को मजबूत बना रही है जिसमें अतीत में इस्तीफों और फेरबदल का सिलसिला देखने को मिला था।

घरेलू एयरलाइनों ने अप्रैल में जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अवसरों का लाभ उठाया, क्योंकि इससे व्यस्त हवाई अड्डों पर भी स्लॉट उपलब्ध हुए और साथ ही उन्हें प्रशिक्षित पायलटों को अपने साथ जोड़ने का मौका मिला।

घरेलू और विदेशी एयरलाइनों ने जेट में काम कर चुके 1,600 पायलट नियुक्त किए।

विमानन विश्लेषकों का कहना है कि पायलट प्रशिक्षण के संदर्भ में डीजीसीए नियमों में बदलाव और हवाई अड्डे पर एंट्री पास जारी किए जाने की प्रक्रिया में तेजी आने से घरेलू और विदेशी पायलटों के इस्तेमाल में सुधार आएगा।

बहुराष्ट्रीय व देसी दवा कंपनियों ने किया बेहतर प्रदर्शन

आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 12 महीनों में बहुराष्ट्रीय दवा निर्माताओं ने भी वृद्धि दर के संदर्भ में भारतीय बाजार में समान रूप से शानदार प्रदर्शन किया

सोहिनी दास
मुंबई, 31 दिसंबर

दवा बाजार

- भारतीय कंपनियों के लिए सालाना कारोबार वृद्धि 9.9 प्रतिशत रही, जबकि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए यह 9.7 प्रतिशत थी
- पिछले 12 महीनों में पेश किए गए कुल 2,466 ब्रांडों में भारतीय दवा निर्माताओं का बड़ा योगदान था

घरेलू दवा निर्माताओं का देश के दवा बाजार में 80 प्रतिशत का योगदान है और ब्रांड पेशकशों के संदर्भ में भी इनकी अच्छी भागीदारी है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 महीनों में बहुराष्ट्रीय दवा निर्माताओं ने भी वृद्धि दर के संदर्भ में भारतीय बाजार में समान रूप से शानदार प्रदर्शन किया।

बाजार शोध फर्म एआईओसीडी एडब्ल्यूएसीएस से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, नवंबर 2019 (पिछले 12 महीनों के लिए) में भारतीय कंपनियों के लिए सालाना कारोबार वृद्धि 9.9 प्रतिशत रही, जबकि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए यह 9.7 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान, कुल दवा बाजार 9.8 प्रतिशत तक बढ़ा। पिछले 12 महीनों में पेश किए गए कुल 2,466 ब्रांडों में भारतीय दवा निर्माताओं का बड़ा योगदान था। भारतीय कंपनियों द्वारा 2,357 नए उत्पाद पेश किए गए थे, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के लिए यह आंकड़ा महज 109 था। एमएनसी ने भारतीय बाजार पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया और कुछ कंपनियों ने मुनाफे पर जोर देते हुए ब्रांडों की संख्या में कटौती भी की।

उदाहरण के लिए, ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स (जीएसके फार्मा) ने 2018-19 में 8-10 ब्रांडों की बिक्री की, जिनमें उसके विटामिन सी ब्रांड सेलिन और एंटी-इन्फेक्टिव ब्रांड सेप्ट्रान शामिल थे, क्योंकि उसने भारत में ब्रांडों की संख्या घटाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जीएसके फार्मा के उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया) एवं प्रबंध निदेशक अन्नास्वामी वैधीश ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट में कहा, 'हमने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को अनुकूल बनाया है और उन प्रमुख ब्रांडों की पहचान की है जिनके लिए संसाधन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।' जीएसके फार्मा के शीर्ष-10 ब्रांडों का उसके कुल राजस्व में 54.8 प्रतिशत का योगदान है। इसी तरह, फाइजर के लिए उसके शीर्ष-10 ब्रांडों का उसके कारोबार में 50.4 प्रतिशत योगदान है और उसके बीकॉसूल (विटामिन), कोरेक्स डीएक्स (कफ सीरप), और जेलुसिल (एंटासिड) ने दो अंक की वृद्धि दर्ज की है।

आईएलऐंडएफएस बोर्ड को 50 प्रतिशत रिकवरी की उम्मीद

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के नए बोर्ड को कंपनी के कुल कर्ज में से 50 प्रतिशत की रिकवरी की उम्मीद है। कंपनी पर 94,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। साथ ही, बोर्ड ने कर्ज के बड़े हिस्से का समाधान करते हुए जुलाई 2020 तक कंपनी की समाधान प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद जताई है।

कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्याधिकारी तथा प्रबंध निदेशक उदय कोटक की अगुवाई वाले बोर्ड ने चरणबद्ध स्तर पर कई कदम उठाए हैं जिसमें 'संकल्प, पुनर्गठन एवं वसूली' शामिल है जिससे ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत समूह स्तरीय समाधान के लिए किसी भी जरूरी कानून ढांचे की आवश्यकता के बिना ही कंपनी के कर्ज को कम किया जा सके।

मंगलवार को सालाना आम बैठक में आईएलऐंडएफएस के शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कोटक ने कहा, 'संकट में फंसी परिसंपत्तियों के लिए समूह आधारित समाधान प्रक्रिया अपनाने के लिए आईएलऐंडएफएस समूह विशेष मामले के तौर पर उभरा है।' अभी तक सात पवन ऊर्जा संबंधित विशेष उपयोग वाहनों (एसपीवी) में करीब 4,300 करोड़ रुपये कीमत के आईएलऐंडएफएस समूह के शेयरों की बिक्री की जा चुकी है। *बीएस*

अनिश्चितता के बीच बॉन्ड, रुपये के लिए महत्त्वपूर्ण रहा साल 2019

अनूप रॉय
मुंबई, 31 दिसंबर

बॉन्ड और रुपये का लेखाजोखा

- वर्ष के अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉन्ड प्रतिफल में नरमी लाने के लिए विशेष ओएमओ की पेशकश की
- लेकिन यह केंद्रीय बैंक द्वारा इस्तेमाल किया गया एकमात्र विकल्प नहीं था। मार्च में, उसने अपने नए नकदी विकल्प के तौर पर मुद्रा की अदला-बदली की भी पेशकश की थी
- डॉलर की तुलना में रुपये की शुरुआत 69.44 पर हुई और 27 दिसंबर को यह 71.32 पर बंद हुआ

वर्ष 2019 दिलचस्प रहा जिसमें वैश्विक के साथ साथ घरेलू कारकों का परिसंपत्ति वर्गों की वैल्यू के निर्धारण में समान योगदान देखा गया। वर्ष के अंत में, भारतीय केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड प्रतिफल में नरमी लाने के लिए विशेष मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) की पेशकश की।लेकिन यह केंद्रीय बैंक द्वारा इस्तेमाल किया गया एकमात्र विकल्प नहीं था। मार्च में, उसने अपने नए नकदी विकल्प के तौर पर मुद्रा की अदला-बदली की भी पेशकश की थी। आरबीआई ने बैंकों के साथ 10 अरब डॉलर की अदला-बदली की।

डॉलर की तुलना में रुपये की शुरुआत 69.44 पर हुई और 27 दिसंबर को यह 71.32 पर बंद हुआ। वर्ष के ज्यादातर समय, अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव का उभरते बाजारों की मुद्राओं पर असर बना रहा, और रुपया भी इससे अलग नहीं रहा। यह तनाव अब दूर हो चुका है। कैलेंडर वर्ष 2019 की पहली छमाही में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर प्रतिशोध के तौर पर शुल्क लगाए थे।

वर्ष के शुरू में 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 7.418 प्रतिशत पर था और यह आखिर में लगभग 6.5 प्रतिशत पर रहा।

यह वह अवधि भी थी जब अमेरिका में प्रतिफल की रफ्तार विपरीत दिखी, जिससे वैश्विक तौर पर मंदी की चिंता गहरा गई। भारतीय बॉन्डों पर भी इस घटनाक्रम का असर पड़ा, लेकिन यह केंद्रीय बैंक द्वारा दर कटौती से सीमित रहा। 2019 में, आरबीआई ने दरों में 135 आधार अंक तक की कटौती की। इससे 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 90 आधार अंक घटा। हालांकि दर कटौती के परिणामस्वरूप अल्पावधि प्रतिफल में 137 आधार अंक की कमी आई। बॉन्ड प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने विशेष ओएमओ की पेशकश की।

शुक्रवार को जारी हुई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) से संकेत मिला है कि वैश्विक रूप से कमजोर प्रतिफल उत्साहित होने की वजह नहीं है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर, खासकर उभरते बाजारों में जोखिम बढ़ रहा है।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) बद्रीश कुल्हाली ने कहा, 'नए वर्ष के लिए परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आर्थिक वृद्धि में मध्यम सुधार आने की संभावना है, जबकि मुद्रास्फीति स्थिर रहने या मौजूदा स्तरों के आसपास रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति में और ज्यादा नरमी की गुंजाइश काफी सीमित दिख रही है।' जनवरी और मार्च के बीच बाजारों को सरकार से कम से कम 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की उम्मीद है। एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक में एएलएम प्रमुख देवेंद्र दास ने कहा, 'अनुमान है कि आरबीआई की मदद से बॉन्ड बाजार नए साल में बेहतर प्रदर्शन करेगा। आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति में नरमी पर जोर दिया है। लेकिन राजकोषीय चिंता से वृद्धि की रफ्तार सीमित होगी।'

2019 में वैश्विक घटनाक्रमों से रुपया प्रभावित हुआ था, और 2020 में भी यह स्थिति बरकरार रह सकती है। रुपये का पोर्टफोलियो प्रवाह से प्रत्यक्ष संबंध है, और आरबीआई ने मजबूत पोर्टफोलियो प्रवाह की वजह से 455 अरब डॉलर का भंडार जमा किया है, लेकिन यदि पूंजी प्रवाह में निकासी होती है तो इस भंडार में कमी आ सकती है।

दबाव वाली संपत्तियों के लिए एसबीआई का फंड

भारतीय स्टेट बैंक की फंड प्रबंधन इकाई एसबीआईकैप वेंचर्स 2 अरब डॉलर का फंड बनाएगी

सुब्रत पांडा और अभिजित लेले
मुंबई, 31 दिसंबर

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की योजना नए साल में दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए फंड पेश करने की है और बैंक संस्थागत निवेशकों से रकम जुटाने के लिए वैश्विक साझेदार को जोड़ेगा।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, हम अपने फंड प्रबंधन कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। अभी समूह की फंड प्रबंधन इकाई एसबीआईकैप वेंचर्स एक रियल्टी फर्म का प्रबंधन कर रही है। वह दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए फंड लाने पर भी विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, फंडों के प्रबंधन के लिए एसबीआईकैप वेंचर्स क्षमता सृजित कर रही है। दबाव वाली परिसंपत्तियों के फंड का आकार दबाव वाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार समर्थित ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) जैसा होने की संभावना है। इस फंड का आकार सांकेतिक तौर पर करीब 2 अरब डॉलर का हो सकता है।

एसबीआई कैप वेंचर्स दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए तभी फंड पेश कर सकती है जब उसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदार की प्रतिबद्धता मिल जाए। इस पर बातचीत चल रही है। कुमार ने कहा, रियल्टी फंड ने हमें काफी आत्मविश्वास से भर दिया है।

फंड प्रबंधन कारोबार का विस्तार करेगा एसबीआई

- अभी एसबीआई समूह की फंड प्रबंधन इकाई एसबीआईकैप वेंचर्स एक रियल्टी फर्म का प्रबंधन कर रही है
- दबाव वाली परिसंपत्तियों के फंड का आकार दबाव वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार समर्थित ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) जैसा होने की संभावना है
- इस फंड का आकार करीब 2 अरब डॉलर का हो सकता है
- एसबीआई कैप वेंचर्स दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए तभी फंड पेश कर सकती है जब उसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदार की प्रतिबद्धता मिल जाए
- इस पर बातचीत चल रही है और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि रियल्टी फंड ने हमें काफी आत्मविश्वास से भर दिया है

नवंबर 2019 में घोषित रियल्टी एआईएफ का इरादा दबाव वाली हाउसिंग परियोजनाओं के लिए आखिरी समय में जरूरी पूंजी मुहैया कराने का है। फंड पहले ही 10,530 करोड़ रुपये जुटा चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम और एसबीआई ने इसमें 10-10 फीसदी का योगदान किया है। चार परियोजनाओं की पहचान हो गई है और जांच परख के बाद फंड जारी किए जाएंगे।

साल 2016 में एसबीआई ने दबाव वाली परिसंपत्तियों में निवेश के लिए 1 अरब डॉलर की शुरुआती प्रतिबद्धता के साथ कनाडा की ब्रुकफील्ड ऐसेट मैनेजमेंट के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए गठजोड़ का ऐलान किया था। लेकिन यह गठजोड़ नहीं हो पाया।

कुमार ने कहा, भारतीय दबाव वाली परिसंपत्तियों के बाजार और दबाव वाली परिसंपत्तियों की आपूर्ति, नियामकीय पारदर्शिता और मजबूती, अन्य वैश्विक परिसंपत्तियों में निवेश के मुकाबले ज्यादा रिटर्न की क्षमता, विदेशी पूंजी की दिलचस्पी बढ़ाने वाले कारक हैं। कुमार ने कहा, दिवालिया संहिता काफी कामयाब रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने हर मसले को स्पष्ट किया है। रुचि सोया और रतन इंडिया पावर का समाधान दिसंबर तिमाही में हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस और आलोक इंडस्ट्रीज जैसे मामलों का समधान हो रहा है और यह मार्च-जून 2019 में पूरा हो सकता है। भारत में लंबी आर्थिक सुस्ती परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार टाल सकता है और बैंकों का एनपीए सितंबर 2019 के 9.3 फीसदी के मुकाबले सितंबर 2020 में बढ़कर 9.9 फीसदी पर पहुंच सकता है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट से मिली।

अर्न्स्ट ऐंड यंग के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दबाव वाली परिसंपत्ति का बाजार 150 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जो निवेश का भारी संभावना का संकेत दे रहा है। यह विदेशी पूंजी के लिए बड़े मौके सामने रखता है, जो या तो आईबीसी के जरिये या फिर अदालत के बाहर वैकल्पिक निपटान आदि के जरिए इसमें भागीदारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 7 जून 2019 को जारी दबाव वाली परिसंपत्तियों पर आरबीआई के संशोधित ढांचे में इससे जुड़ी कई चिंताओं का समाधान कर दिया गया है।

रहेजा-ब्लैकस्टोन की फर्म ने जमा कराए रीट आईपीओ के दस्तावेज

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 31 दिसंबर

- इस इश्यू के जरिये करीब 3,500 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये नए शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे
- इससे पहले ब्लैकस्टोन जेवी एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ने इस साल की शुरुआत में रीट उतारा था और 4,750 करोड़ रुपये जुटाए थे

के. रहेजा समूह की तरफ से प्रवर्तित माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स ने अपने रीट (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के सार्वजनिक निर्गम के लिए पेशकश दस्तावेज का मसौदा जमा करा दिया है। रीट में ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट पार्टनर्स प्रमुख निवेशकों में से एक है।यह देश का दूसरा रीट है जो सार्वजनिक निर्गम के साथ आ रहा है। इससे पहले ब्लैकस्टोन जेवी एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ने इस साल की शुरुआत में रीट उतारा था और 4,750 करोड़ रुपये जुटाए थे।

सूत्रों ने कहा कि इस इश्यू के जरिये करीब 3,500 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये नए शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा, कितनी हिस्सेदारी का विनिवेश होना है, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। साल 2017 में ब्लैकस्टोन ने के. रहेजा कॉर्प की सिलेक्ट कॉमर्शियल इनकम प्रोड्यूसिंग ऑफिस पोर्टफोलियो की 15 फीसदी हिस्सेदारी ली थी, जो 3 करोड़ वर्गफुट में फैला है। ब्लैकस्टोन का अन्य संयुक्त उद्यम पंचशील रियल्टी और सलारपुरिया सत्व के साथ है और सूत्रों का कहना है कि ये भी भविष्य में रीट पेश कर सकती हैं।

रीट म्युचुअल फंडों की तरह होते हैं, जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजों में होती है। ये कर देनदारी कम करने वाले होते हैं क्योंकि ये अपना 90 फीसदी मुनाफा लाभांश के तौर पर वितरित करते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर अगले तीन साल में अपनी किराए वाली वाणिज्यिक परिसंपत्तियां रीट के के जरिए सूचीबद्ध करा सकते हैं। यह कहना है रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का। एनारॉक कैपिटल के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी शोभित अग्रवाल ने कहा, वाणिज्यिक रीट के जरिए भारतीय रियल एस्टेट के लिए अगले तीन साल में 25 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं। इसमें सात शहरों की ए श्रेणी वाली किराए वाली कार्यालय परिसंपत्तियों का 15 करोड़ वर्गफुट से ज्यादा सूचीबद्ध हो सकता है। अभी सात अग्रणी शहरों दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद और पुणे की 55 करोड़ वर्गफुट परिसंपत्तियां रीट के तहत सूचीबद्ध हो सकती हैं।

एसएमई आईपीओ में 73 फीसदी की गिरावट

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 31 दिसंबर

एसएमई आईपीओ

साल	बीएसई में सूचीबद्ध		एनएसई में सूचीबद्ध		कुल	
	आईपीओ की संख्या	रकम (करोड़ रु.)	आईपीओ की संख्या	रकम (करोड़ रु.)	आईपीओ की संख्या	रकम (करोड़ रु.)
2013	33	300.6	2	34.5	35	335.2
2014	38	234.4	2	32.4	40	266.8
2015	37	215.7	6	44.5	43	260.2
2916	43	351.4	24	185.9	67	537.3
2017	55	486.4	78	1,193.1	133	1,679.5
2018	63	961.6	78	1,325.3	141	2,286.9
2019	35	442.7	14	174.5	49	617.2

स्रोत : प्राइम डेटाबेस

छोटे व मझोले उद्यम (एसएमई) के सार्वजनिक शेयरों की बिक्री से संग्रह साल 2019 में एक साल पहले के मुकाबले 73 फीसदी की गिरावट के साथ 617 करोड़ रुपये रह गया क्योंकि निवेशकों के बीच जोखिम को लेकर प्रतिकूलता और मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट से अवधारणा पर असर पड़ा।

साल 2019 में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या पिछले कैलेंडर वर्ष के मुकाबले एक तिहाई घट गई। पांच साल में यह पहला मौका है जब ऐसे शेयरों की बिक्री से संग्रहित रकम घटी है। साल 2019 में संग्रहित रकम हालांकि साल 2013, 2014, 2015 और 2016 के मुकाबले ज्यादा रही है। कैलेंडर वर्ष 2018 एसएमई आईपीओ के लिए सबसे अच्छा वर्ष रहा जब 141 आईपीओ के जरिये 2,287 करोड़ रुपये जुटाए गए।

एसएमई में सक्रिय पैंटोमैथ एडवाइजरी सर्विसेज ग्रुप के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक महावीर लूणावत ने कहा, मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट के बाद एसएमई आईपीओ में सुस्ती प्राथमिक बाजार के कुल सेंटिमेंट और निवेशकों के बीच जोखिम को लेकर प्रतिकूलता के मुताबिक है।

लूणावत ने कहा, आईपीओ की संख्या के लिहाज से मुख्य एक्सचेंजों के मुकाबले एसएमई क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा गतिविधियां देखने को मिली है। एसएमई आईपीओ से कई कंपनियां रकम जुटाने की प्रतीक्षा कर रही हैं और अगले वित्त वर्ष में इसमें सुधार की उम्मीद है।

इस साल सूचीबद्ध हुई कंपनियों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। 24 कंपनियां हरे निशान में हैं और पांच में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दूसरी ओर 21 कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और सात कंपनियां 50 फीसदी से ज्यादा गंवा चुकी हैं। इन कंपनियों का औसत रिटर्न 21.5 फीसदी रहा है जबकि बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स का 6.8 फीसदी।

पैंटोमैथ के मुताबिक, ट्रेडिंग ऐंड डिस्ट्रिब्यूशन, रिटेल और टेक्सटाइल का एसएमई कैपिटल मार्केट में इस साल वर्चस्व रहा। कैलेंडर वर्ष 2019 में सूचीबद्ध एसएमई की कीमतों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई है।

उच्च रिटर्न की संभावना के बावजूद विशेषज्ञों ने कहा कि एसएमई शेयर में पूरी पूंजी डूबने का जोखिम भी है। इन फर्मों का विश्लेषण चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि विश्लेषक इन पर नजर नहीं रखते और सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को खुद ही फंडामेंटल और प्रवर्तकों की साख आदि का आकलन करना होता है। एक फर्म के शोध प्रमुख ने कहा, निवेशकों को एसएमई के क्षेत्र में चयनात्मक रवैया अपनाना चाहिए और निवेश से पहले उन कारोबारी मॉडल का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए जिसके जरिए कंपनी अपना परिचालन करती है। एसएमई कई समस्या से जूझ रही हैं मसलन नकदी का संकट और संस्थागत भागीदारी में सुस्ती।

कार्वी के खिलाफ डीआरटी पहुंचा ऐक्सिस बैंक

जश कृपलानी
मुंबई, 31 दिसंबर

आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब ऐक्सिस बैंक ने भी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) का दरवाजा खटखटाया है। हाल में ब्रोकरेज फर्म को डीआरटी में आईसीआईसीआई बैंक की याचिका के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय से आंशिक राहत मिली है। आईसीआईसीआई बैंक ने 629 करोड़ रुपये की वसूली के लिए डीआरटी का दरवाजा खटखटाया था। डीआरटी ने 9 दिसंबर के आदेश में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के पास 629 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था, जिसमें नाकाम होने पर उसकी परिसंपत्तियां जब्त की जाएंगी।

7 दिसंबर 2019 को कार्वी के ऊपर ऐक्सिस बैंक का 81 करोड़ रुपये बकाया था, जिसे शेयर के बदले ओवरड्राफ्ट के तौर पर दिया गया था। लेनदार डीआरटी से संपर्क कर रहे हैं, जब उन्हें प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिली। इससे पहले एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने राहत के लिए सैट का दरवाजा खटखटाया था।

इस साल 175 करोड़ रुपये का मार्केटिंग अभियान चलाएगी अपग्रेड

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 31 दिसंबर

भारत में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन उच्च शिक्षा बाजार का लाभ उठाने के लिए प्रख्यात मीडिया उद्यमी एवं पूर्व यूटीवी संस्थापक रॉनी स्क्रूवाला के निवेश वाले स्टार्टअप अपग्रेड ने वर्ष 2020 में 175 करोड़ रुपये के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग अभियान की योजना तैयार की है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों (टेलीविजन, डिजिटल और प्रिंट) से जुड़े इस अभियान का मकसद डेटा, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षेत्रों में अपग्रेड के ऑनलाइन उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के बारे उसके संभावित छात्रों यानी कामकाजी पेशेवरों के बीच जागरूकता पैदा करना है।

स्क्रूवाला द्वारा मयंक कुमार, रविजोत चुघ और फाल्गुन कोम्पाली के साथ मिलकर तैयार की गई अपग्रेड ने कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के तौर पर स्वयं की पहचान बनाई है। यह ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उच्च शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर कामकाजी पेशेवरों को स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्रियां भी प्रदान कर रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, एमआईसीए, आईएमटी और एनएमआईएमएस समेत कुछ प्रमुख कैम्पसों की भागीदारी में अपग्रेड ऑनलाइन उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम मुहैया कराता है और इन शैक्षिक कार्यक्रमों में कामकाजी पेशेवर अपनी नौकरी बरकरार रखते हुए हिस्सा ले सकते हैं।

सड़क-ऊर्जा क्षेत्र को मिली सरकार से सौगात

मेघा मनचंदा और शाइन जैकब
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार सड़क क्षेत्र को वर्ष 2019 के आखिरी दिन अच्छी सौगात दी। उन्होंने 19.63 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में केंद्र एवं राज्यों की 39-39 फीसदी और निजी क्षेत्र की 22 फीसदी परियोजनाएं शामिल हैं।

फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी ने कहा, 'यह अच्छा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है।'

सरकार ने बुनियादी ढांचा विजन 2025 में सुदूरवर्ती इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ना एवं एक्सप्रेसवे के जरिये ट्रंक कनेक्टिविटी, प्रमुख आर्थिक गलियारे, रणनीतिक क्षेत्र और पर्यटन स्थल आदि शामिल हैं।

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपने बयान में कहा, 'भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश अत्यधिक बढ़ने के आसार हैं क्योंकि अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025) के दौरान 105 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।' ऐसे समय जब आर्थिक वृद्धि घट रही है, तब बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने से वृद्धि में तेजी आ सकती है। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पहले से ही एक पड़ी विकास योजना पर काम चल रहा है। वहीं बहुत से राज्य भी बड़ी सड़क विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी रेलवे में रेलवे लाइनों के अपग्रेडेशन पर नियमित पूंजीगत व्यय के अलावा रेल स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बुलेट ट्रेन परियोजना के चलते अगले पांच वर्षों में बड़ी पूंजीगत खर्च होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे क्षेत्र में 13.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है, जिसमें केंद्र सरकार के 87 फीसदी योगदान देने के आसार हैं। इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 फीसदी और राज्यों की महज एक फीसदी है। मौजूदा रफ्तार से भारतीय रेलवे 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने से चूक सकता है क्योंकि वर्ष 2025 तक आधे लक्ष्य को भी हासिल करना संभव नहीं होगा। भारतीय रेलवे के पूर्व वित्त आयुक्त आर शिवदसन ने कहा, 'रेलवे उन क्षेत्रों में से एक होगा, जहां निजी निवेश सबसे कम होगा।'

सड़क परियोजनाओं की घोषणा

- वित्त मंत्री सितारमण ने 19.63 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की
- इन परियोजनाओं में केंद्र एवं राज्यों की 39-39 फीसदी और निजी क्षेत्र की 22 फीसदी परियोजनाएं शामिल

सरकार लोगों तक ऊर्जा पहुंचाने पर देगी जोर

श्रेया जय
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजनाओं में बिजली क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा और इस क्षेत्र पर 24 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। सरकार का मकसद ऊर्जा की निरंतर और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इसमें बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र का होगा।

सरकार बिजली क्षेत्र पर ऐसे समय जोर दे रही है, जब ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश अब के सबसे निचले स्तर पर है। इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये परिसंपत्तियां ऋणग्रस्त हैं। वहीं नवीकरण ऊर्जा को लेकर भी निवेशकों का रुझान कमजोर पड़ रहा है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से बिजली वितरण में निजी भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं का खाका पेश किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 2025 तक बढ़कर 1,616 किलोवाट घंटे हो जाएगी, जो इस समय 1,181 किलोवाट घंटा है।

विजन 2025 में सभी परिवारों, उद्योगों, व्यवसायों और कृषि को 24 घंटे स्वच्छ और सस्ती बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि कुल बिजली उत्पादन 2025 तक बढ़कर 619 गीगावाट हो जाएगा, जिसमें 50 फीसदी योगदान ताप बिजली और 39 फीसदी नवीकरणीय स्रोतों का होगा।

ऑनलाइन किराना को जियो मार्ट की चुनौती

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 31 दिसंबर

एशिया का सबसे धनी व्यक्ति ई-कॉमर्स में खलबली मचाने जा रहा है। इंटरनेट क्षेत्र पिछले एक दशक से सबसे तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी एक ऑफलाइन-टू-ऑनलाइन कारोबार शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम जियो मार्ट होगा। जियो मार्ट शुरू में मुंबई के चुनिंदा स्थानों पर पैकेट बंद उपभोक्ता उत्पादों और रसोई के सामान की ग्राहकों को आपूर्ति करेगी।

जियो मार्ट में सामान की आपूर्ति हजारों किराना स्टोर करेंगे। इन स्टोरों ने इंटरनेट से जुड़े पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और इन्वेंट्री प्रबंधन डिवाइस का इस्तेमाल करके जियो पर खुद को पंजीकृत किया है। किराना स्टोर अपने माल को ऑनलाइन दर्ज करेंगे, नए स्टॉक के लिए ऑर्डर देंगे, ग्राहकों को ऑफर भेजेंगे और जियो मार्ट प्लेटफॉर्म के जरिये ऑनलाइन बिक्री को प्रबंधित करेंगे।

एक सूत्र ने कहा कि जियो मार्ट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन अगले कुछ हफ्तों में पेश किए जाने की संभावना है। इसे माई जियो और जियो मनी एप्लीकेशनों से भी जोड़ा जाएगा। मुंबई में सोमवार को जियो के ग्राहकों को जल्द साइन-अप करने के एवज में शुरुआती ऑर्डरों पर 3,000 रुपये तक की बचत के ऑफर मिले हैं।

साइन अप पेज जियो डॉट कॉम या जियो मार्ट पर खुला है। इस नए उद्यम की टैग लाइन 'देश की नई दुकान' है। इसमें किराने के 50,000 से अधिक उत्पाद, मुफ्त डिलिवरी, कम कीमत और आसानी से वापसी की पेशकश की गई है। जियो मार्ट को सबसे पहले नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में शुरू किया जा रहा है।

जियो मार्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग (सीमित क्षेत्र में सेवा) से वर्षों से रिलायंस के ई-कॉमर्स में उतरने के कयासों की पुष्टि होती है। माना जा रहा है कि रिलायंस की 'संचार, सामग्री और वाणिज्य' की रणनीति में जियो अहम हिस्सा होगी।

रिलायंस ने वर्ष 2016 में जियो शुरू करने के बाद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, संगीत, होम ब्रॉडबैंड और टीवी जैसी कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी के फिलहाल 36 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं, जिसकी मदद से वह कोई भी इंटरनेट सेवा शुरू करने की ताकत रखती है।

जियो मार्ट ने घरेलू सामान और किराना स्टोरों पर जोर दिया है। इस तरह वह सीधे बिग बास्केट और उड़ान जैसी स्टार्टअप को टक्कर देगी। अलीबाबा समर्थित बिग बास्केट बड़ी किराने का सामान डिलिवर करने वाली कंपनी है, जिसकी कारोबारी मौजूदगी 26 शहरों में है। कंपनी का मूल्यांकन 2.3 अरब डॉलर है। वहीं उड़ान तेजी से बढ़ती बी2बी ई-कॉमर्स स्टार्टअप है, जो छोटे खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और थोक विक्रेताओं का डिजिटलीकरण कर रही है।

जियो अपने पीओएस समाधान के जरिये पिछले एक साल से देश भर में किराना स्टोरों को जोड़ रही है, जिन्हें जनवरी में वाइब्रेंट समिट ने पेश किया गया था। इस कार्यक्रम में अंबानी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के गठजोड़ से एक नए ई-कॉमर्स उद्यम पर काम कर रही है।

एक सूत्र ने कहा, 'अकेले नवी मुंबई में ही करीब 10,000 कारोबारियों ने साइन-अप किया है।' एक व्यक्ति ने कहा कि देश भर में किराना स्टोरों को जोड़ा गया है, लेकिन शुरुआत में इसे मुंबई में शुरू किया जा रहा है क्योंकि यहां सभी सिस्टम तैयार हो चुका है।

बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

- जियो मार्ट पैकेट बंद उपभोक्ता उत्पादों और रसोई के सामान की करेगी आपूर्ति
- सबसे पहले नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में किया जा रहा है शुरू
- जियो मार्ट में सामान की आपूर्ति हजारों किराना स्टोर करेंगे

चालू खाते के घाटे में कमी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 31 दिसंबर

भारत का चालू खाते का घाटा (सीएडी) 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.9 फीसदी रह गया जो जून तिमाही में 2 फीसदी पर था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सीएडी में यह गिरावट मुख्य तौर पर व्यापार घाटे में कमी आने की वजह से आई है।

एक वर्ष पहले दूसरी तिमाही में सीएडी जीडीपी का 2.9 फीसदी रहा था। पूरे संदर्भ में देखें तो 2019-20 की दूसरी तिमाही में सीएडी 6.3 अरब डॉलर पर आ गया जो एक वर्ष पहले 19 अरब डॉलर और उससे पिछली तिमाही में 14.2 अरब डॉलर रहा था।

दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा 38.1 अरब डॉलर रहा जो एक वर्ष पहले 50 अरब डॉलर रहा था। कंप्युटर, यात्रा और वित्तीय सेवाओं से शुद्ध कमाई में इजाफा होने से सेवाओं की कुल प्राप्तियों में सालाना आधार पर 0.9 फीसदी का इजाफा हुआ। रिजर्व बैंक ने कहा कि निजी अंतरण प्राप्तियों मुख्य तौर पर विदेशों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भेजे जाने वाला धन बढ़कर 21.9 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले वर्ष के स्तर से 5.2 फीसदी अधिक है। कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 7.4 अरब डॉलर रहा जो कि 2018-19 की दूसरी तिमाही के लगभग बराबर स्तर पर ही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में शुद्ध आवक 2.5 अरब डॉलर रहा जबकि एक वर्ष पहले की तिमाही में 1.6 अरब डॉलर बाजार से निकाले थे। ऐसा ऋण बाजार में अपेक्षाकृत उच्च निवेश के कारण हुआ है।

बाह्य वाणिज्यिक उधारी बढ़कर 3.2 अरब डॉलर हो गई जबकि यह पिछले वर्ष की तिमाही में 2 अरब डॉलर रही थी। दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा के आरक्षित भंडार में 5.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

2019-20 की छमाही में सीएडी घटकर जीडीपी का 1.5 फीसदी रह गया जो पिछले वर्ष की पहली छमाही में 2.6 फीसदी रहा था। इस दौरान व्यापार घाटा घटकर 84.3 अरब डॉलर हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 95.8 अरब डॉलर रहा था।

आरबीआई के मुताबिक सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 0.9 फीसदी पर आया

दूरसंचार विभाग की 5जी परीक्षण पर बैठक

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिक के परीक्षण की आगे की राह पर विचार विमर्श करने के लिए दूससंचार सेवा प्रदाताओं और हुआवेई सहित विभिन्न नेटवर्क उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ मंगलवार को बैठक की।

यह बैठक 5-जी परीक्षण के लिए कंपनियों के नाम अधिसूचित करने के सरकार के सोमवार के निर्णय के ठीक बाद बुलाई गई। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली। एक दूरसंचार कंपनी के अधिकारी ने कहा कि सभी परिचालकों ने बैठक में भाग लिया। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि सरकार सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सुपर-फास्ट स्पीड 5 जी नेटवर्क के परीक्षण के लिए एयरवेव आवंटित करेगी। *भाषा*

यूपीआई, रुपे इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना

सोमेश झा और समरीन अहमद
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 31 दिसंबर

कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली उन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो घरेलू रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करती हैं। इन कंपनियों को इसके लिए रोजना 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियम 1 फरवरी, 2020 से प्रभावी हो जाएगा।

इस अधिसूचना में कहा गया है, 'निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने के लिए सुविधा तैयार करने और उसको परिचालन में लाने के लिए पर्याप्त समय देते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि 31 जनवरी, 2020 तक इस सुविधा को स्थापित कर इसका परिचालन शुरू करने वाले कारोबारियों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।'

सरकार ने कहा है कि इस कदम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी।

इसी हफ्ते वित्त मंत्री ने रुपे और यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिये लेनदेन करने पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्कों को समाप्त करने की घोषणा की थी जो बुधवार से प्रभावी हो रहा है। भारतीय भुगतान परिषद ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। यह संस्था देश में भुगतान और फिनटेक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

कोर सेक्टर का उत्पादन लगातार तीसरे महीने घटा

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

अर्थव्यवस्था के आठ कोर सेक्टर का उत्पादन नवंबर में लगातार तीसरे महीने 1.5 फीसदी घटा है। इसकी वजह यह है कि रिफाइनरी उत्पाद और बिजली जैसे अहम क्षेत्रों में वृद्धि धीमी है या गिर रही है। इन क्षेत्रों के उत्पादन में अक्टूबर में रिकॉर्ड 5.8 फीसदी और सितंबर में 5.2 फीसदी गिरावट आई थी। इसके नतीजतन चालू वित्त वर्ष 2020 में नवंबर तक कोर सेक्टरों की समग्र वृद्धि शून्य रही है, जो पिछले साल 5.1 फीसदी थी।

अर्थशास्त्रियों ने चेताया कि ताजा आंकड़े यह संकेत देते हैं कि चालू औद्योगिक मंदी दूर होने में समय लगेगा। वर्ष 2011-12 या 2004-05 को आधार वर्ष मानते हुए पांच फीसदी से अधिक गिरावट सूचकांक के इतिहास में अप्रत्याशित है। इंडिया रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, 'यह पहला ऐसा उदाहरण है, जब 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए आठ कोर बुनियादी ढांचा उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा निराशाजनक चीज लगातार चार महीनों से बिजली के उत्पादन में गिरावट आना है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है।'

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बिजली का उत्पादन 5.7 फीसदी कम हुआ है। बिजली उत्पादन में गिरावट अगस्त में महज 0.9 फीसदी थी, जो अक्टूबर में 12.2 फीसदी पर पहुंच गई। विनिर्माण में सुस्ती से बिजली की मांग में भारी कमी आई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट स्थिर बनी हुई है। यह अक्टूबर में 2.1 फीसदी रही।

भरोसे के संकट से जूझ रहा विश्व व्यापार संगठन

डब्ल्यूटीओ पर लेकर सदस्य देशों का भरोसा नहीं रह गया है और यही वजह है कि इसमें सुधार कई देशों के एजेंडे में सबसे ऊपर है

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 31 दिसंबर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का गठन 1 जनवरी, 1995 को किया गया था और यह दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा सुधार था। अब इसकी 25वीं वर्षगांठ पर इसी संस्था में सुधार कई देशों के व्यापार एजेंडे में सबसे ऊपर है। इनमें अमीर और गरीब दोनों तरह के देश शामिल हैं। डब्ल्यूटीओ में दुनिया का भरोसा ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार एवं तटकर पर सामान्य समझौता (गैट) उत्पादों के व्यापार के लिए था लेकिन डब्ल्यूटीओ ने अपना दायरा श्रम, पर्यावरण और बौद्धिक संपदा तक फैला दिया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापार की अपनी सक्षम नीतियों के माध्यम से इसे कुछ वर्ष पहले तक सभी देशों को परामर्श देने के लिए एक मंच प्रदान करने का श्रेय दिया गया था।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कई खेमों में बंटने के बाद डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और रूस जैसी दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में ने अपने अलग खेमे बना लिए हैं। इस बहुस्तरीय संस्था पर हमले के अगुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रहे हैं। डब्ल्यूटीओ विभिन्न खेमों के बीच टकराव को खत्म करने में नाकाम रहा है जिससे दुनिया के सभी देश प्रभावित हुए हैं। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक विवादों के लिए गठित डब्ल्यूटीओ की शीर्ष अदालत भी दिसंबर की शुरुआत में निष्क्रिय हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है।

सात न्यायाधीशों वाली इस अपीलीय संस्था के बचे हुए तीन सदस्यों में से दो सेवानिवृत्त हो गए और इसके साथ ही यह संस्था निष्क्रिय हो गई। यह अरबों डॉलर के वैश्विक व्यापारिक विवादों को निपटाने के लिए सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। इसे बहुस्तरीय व्यापारिक व्यवस्था का मुख्य स्तंभ माना जाता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए डब्ल्यूटीओ का अनोखा योगदान माना जाता है। पिछले दो दशक में इस अपीलीय संस्था ने वैश्विक व्यापार के प्रवाह को आकार दिया है। लेकिन भारत और 116 अन्य देश अमेरिका को यह समझाने में नाकाम रहे हैं कि वह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के खिलाफ लंबे समय से आ रहा अपना विरोध छोड़ दें। इसके लिए सभी देशों के निर्विरोध समर्थन की जरूरत होती है।

लेकिन पिछले तीन वर्षों से अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। उसका कहना है कि इस संस्था ने अमेरिका और विकसित देशों के व्यापक हितों की अनदेखी की है। यह विरोध तबसे और तेज हो गया है जबसे डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका द्वारा चीन और अन्य व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए एकतरफा शुल्क की आलोचना की है।

डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दासगुप्ता ने पहले कहा था, 'अमेरिका के बड़ा खेल खेल रहा है। एक तरफ वह इस विवाद निपटान संस्था में याचिका दायर कर रहा है और दूसरी ओर उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति रोक रहा है।'

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर लगातार डब्ल्यूटीओ पर हमले करते रहे हैं। उनका आरोप है कि यह संस्था अमेरिका के प्रति निष्पक्ष नहीं है। दिलचस्प बात है कि लाइटहाइजर को 16 वर्ष पहले अपीलीय संस्था में नामांकित किया गया था। हालांकि दूसरे देशों के विरोध के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी।

2019 में उन्होंने डब्ल्यूटीओ के बजट में कटौती की धमकी दी और इस संस्था में चीन के प्रवेश को गलती बताया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की मांगों को नहीं माना गया तो वह डब्ल्यूटीओ से निकल जाएगा। लेकिन वैश्विक व्यापार विवादों को निपटाने की एकमात्र संस्था के तौर पर डब्ल्यूटीओ की क्षमता लंबे समय से क्षीण होती जा रही है। अभी मामलों की सुनवाई में एक साल से अधिक समय लगता है जबकि सरकारें और व्यापार अधिकारी जेनेवा में डेरा डाले रहते हैं। दूसरी ओर छोटे देश खुद को अलग-थलग मानते हैं। उनकी शिकायत रहती है कि उनके मुद्दों को डब्ल्यूटीओ में ज्यादा तरजीह नहीं मिलती है।

25वीं वर्षगांठ पर सुधार की दरकार

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कई खेमों में बंटने के बाद डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर सवाल उठे
- इस बहुस्तरीय संस्था पर हमले के अगुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रहे हैं

- डब्ल्यूटीओ विभिन्न खेमों के बीच टकराव को खत्म करने में नाकाम रहा है जिससे दुनिया के सभी देश प्रभावित हुए

बीएस सूडोकू 3627

			1		4		3	
				3			1	
		9					7	6
1			8	6		2		
8	5						9	4
		2		5	3			8
2	7					6		
	8			4				
	6		5		1			

परिणाम संख्या 3626

5	7	6	3	8	2	9	1	4
4	1	8	9	7	6	5	3	2
3	2	9	4	5	1	6	7	8
2	9	7	1	3	5	4	8	6
8	4	5	6	2	7	3	9	1
1	6	3	8	9	4	7	2	5
9	5	2	7	6	8	1	4	3
6	3	4	2	1	9	8	5	7
7	8	1	5	4	3	2	6	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2185/2190, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4600/4650, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1650/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2210/2220, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1450, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1465, डीएमओ 1062, टरपीन लैस बोल्ड 1560

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1350/1410, खुरपा 1250/1300,चाकू 1250/1310, रसकट 1020/1030, शक्कर 1400/1450, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1300/1350, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खल: सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2220/2225, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4890/4900,

श्रीगंगानगर
गेहूं (देरी) 2100/2125, ग्वार 3950/4000, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2125, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7800/7900, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4300/4400, काबली चना 5000/6000, मूंग 6600/6600,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)131, राइसब्रान (अखाद्य) 128, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1350,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5550, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4075/4100, हरियाणा 4040/4060, राजस्थान 3950/4050, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2245/2250, सरसों 4550/4650 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4075, कपास देशी 5050/5150, कपास नरमा (क्विं.) 5350/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2260/2270, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2500/2525, दाल उड़द छिलका 9500/10900, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5500/5700, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7000/8400, चीन 7500/8100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2230/2240, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 39000/3950, जौ 1775/1780, सरसों 4350/4400, मूंग 6500/6700, गेहूं 2150/2160,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1100/1110, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4400/4450, खल बिनौला मोटी 2500/2600, बिनौला 3000/3400, सरसों तेल 9500/9600, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3900/3950, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 271

विजन 2020

भारत की आर्थिक वृद्धि पिछली पांच तिमाहियों से लगातार सुस्त पड़ती जा रही है और पूर्वानुमानों की मानें तो निकट भविष्य में इसके तेज होने की संभावना काफी कम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यत: सामाजिक एजेंडे वाले कदम उठाए जिन्होंने उन्हें भारी बहुमत दिलाया। लेकिन राज्यों में उनकी पार्टी के सिकुड़ते आधार को उन्हें इसका संकेत मानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की कीमत पर हिंदुत्व के घोषणापत्र को प्राथमिकता देने के जोखिम भी हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर जारी हंगामे के बीच झारखंड में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश के 71 फीसदी से घटकर 35 फीसदी क्षेत्र तक सिमट गई है। यह इस द्विभाजन का सबसे सटीक संकेतक है। झारखंड में मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अभियान में आदिवासी मतदाताओं के बारे में घुमावदार समझ दिखी। बढ़ती बेरोजगारी और नक्सली समस्या यहां की सबसे बड़ी चिंताएं हैं लेकिन शाह इन मुद्दों के बजाय अयोध्या में आसमान छूने वाला मंदिर बनाने की बात करते रहे। इसके पहले भारत की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले राज्य महाराष्ट्र में भी भाजपा पिछली बार से भी कम सीटें जीत पाई और अपने दम पर निर्णायक बहुमत नहीं जुटा पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद उससे नाराज एक पुराने सहयोगी दल की अगुआई में दूसरी सरकार बन गई।

इन दोनों राज्यों में मिली हार राष्ट्रीय एवं राज्यों के चुनाव में फर्क कर पाने की समझ पर सवाल उठाती हैं। यह संभव है कि राष्ट्रीय चुनाव कहीं बड़े एवं अमूर्त विचारों पर लड़े जाएं लेकिन राज्यों के चुनाव अमूमन रोजी-रोटी के मसले पर ही लड़े जाते हैं। वर्ष 2017 में गोवा और कर्नाटक में विधायकों के पाला-बदल के समय भी यह दिखा था। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में मिली शिकस्त भाजपा के लिए चेतावनी होनी चाहिए थी। उन तीनों राज्यों में ग्रामीण असंतोष गहराने का मुद्दा सबसे अहम था। इस असंतोष के लिए वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी और उसके एक साल बाद जीएसटी प्रणाली के जल्दबाजी में क्रियान्वयन को जिम्मेदार माना गया।

मोदी ने 2019 के चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले कृषि आय समर्थन योजना की घोषणा की थी लेकिन वह जमीन से आ रहे संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। इस पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने वायुसेना के विमानों को पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर आतंकी ठिकानों पर हमले करने का बहुत बड़ा दांव खेल दिया। मोदी ने मान लिया कि उन्हें दूसरी बार मिला बहुमत 'अधिक साहसी एवं बड़े हिंदुत्व' के लिए निर्देश-पत्र है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना, जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बांटना, सीएए को पारित कराना और देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन सीएए-एनपीआर जोड़ी पर गैर-भाजपा शासित राज्यों और कुछ गठबंधन सहयोगियों की कड़ी आपत्तियों के बाद मोदी की हिंदुत्व परियोजना राज्यों के हाथों में बंधक बन गई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लंबा अनुभव रखने से मोदी को पता होना चाहिए कि आर्थिक सफलता के लिए जमीनी काम किए बगैर कोई भी सामाजिक एजेंडा हासिल नहीं किया जा सकता है। 2014 में राज्यों पर भाजपा की मजबूत पकड़ से कठिन आर्थिक सुधार करने का सुनहरा मौका मिला था लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया है। सतत वृद्धि के पथ पर बढ़ने के लिए ये सुधार बेहद जरूरी थे। अब वह 'सशक्त भारत' के एजेंडे का विस्तार अर्थव्यवस्था तक कर अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत जैसे युवा देश में बढ़ती बेरोजगारी वर्ष 2020 में मोदी के समक्ष मौजूद चुनौतियों एवं खतरों दोनों को अभिव्यक्त करती है।

विनय सिन्हा

हकीकत से दूर है सत्ता की मानसिकता

सत्ताधारी राजनेताओं की बातें उपदेशात्मक हो जाती हैं। उन्हें सुनकर यह साफ हो जाता है कि वे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

भारत में शासन करने का पहला नियम यह है कि जन प्रतिनिधि सत्ता में आते ही जनता की बातें सुनना बंद कर देते हैं। दूसरा नियम यह है कि कोई समूह जितने लंबे समय तक सत्ता में रहता है, उतना ही अहंकारी और हकीकत से दूर होता जाता है। तीसरा नियम यह कि सत्ताधारी दल के राजनेता एक दूसरे की अनुगूंज बन जाते हैं, भले ही हम सुनने वालों को वह कितना ही मूर्खतापूर्ण और वास्तविकता से परे नजर आए। इन नियमों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस समय हमारे आसपास हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के 2011-13 के अंतिम दिनों को याद कीजिए। व्यापक भ्रष्टाचार, एक जघन्य बलात्कार, आर्थिक मोर्चे पर ठहराव और नीतिगत विफलताओं ने पूरे देश को जकड़ रखा था। इसका विरोध करने के लिए उस दौर में गरीब, व्यस्त और असंवेदनशील लोग भी सड़क पर उतर आए थे। क्या मौजूदा दौर में भी मनोदशा उसी दिशा में बढ़ रही है? संप्रग-2 के दौर के तमाम कारक हमारे बीच मौजूद हैं केवल भ्रष्टाचार को छोड़कर। कुशासन और उद्देश्यविहीन विचलन देखे जा सकते हैं। एक बार फिर जघन्य बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला जारी है, अब अचानक लोगों को नागरिकता और राष्ट्रीय पंजीयन की नई प्रक्रिया से दो-चार होना पड़ सकता है। इसकी कुल लागत 70,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब सरकार का खजाना खाली है। गलत समय पर उठाए गए इस कदम के खिलाफ स्वत: स्फूर्त विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है। ठीक पिछली सरकार की तरह छह साल से सत्ता में बनी हुई यह सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है।

पिछले प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से ईमानदार थे लेकिन वह नागरिकों और कारोबारियों की रोजमर्रा की समस्याओं से दूर नजर आते थे। मौजूदा प्रधानमंत्री भी इससे कतई अलग नहीं नजर आते। उनके मंत्री भी एक सिरे से हकीकत से दूर नजर आते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम किसी सम्राट की तरह बातें किया करते थे। वह आर्थिक कारकों को आदेश देते थे कि वे सक्रिय हों और वह मानो घटनाओं को सुनिश्चित करते थे। कुछ दिन पहले मौजूदा वित्त मंत्री ने भी लगभग वैसी ही टिप्पणी में कहा, 'मैंने सरकारी बैंकों से कहा है कि वे रिवर्स रीपो का इस्तेमाल करने के बजाय ऋण दें।' उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार बैंकों की निर्णय प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने देश के कारोबारी जगत को भी यह 'सलाह' दी कि वे निजीकृत की जा रही सरकारी कंपनियों को लेकर उत्साह दिखाएं। उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे अपने मन का संदेह दूर करें और कारोबारी भावना जागृत करें।

जाहिर है कंपनियां उनकी बात नहीं सुन रहीं। करीब 16 वर्ष पहले तत्कालीन विनिवेश मंत्री अरुण शौरी ने कहा था कि सरकारी कंपनियां कोई ताज में जड़ा आभूषण नहीं हैं बल्कि ये ऐसे घाव हैं जिनसे रक्तस्राव हो रहा है। एक के बाद एक सरकारों के कार्यकाल में उनकी स्थिति और खराब हुई है। ऐसे में किसी से यह कहना कि वह इन कंपनियों के लिए उत्साहित होकर बोली लगाए, हास्यास्पद ही है। उसी दिन प्रधानमंत्री ने औद्योगिक संगठन एसोचैम के सदस्यों से कहा कि वे निर्भय होकर निवेश का निर्णय करें। सुनने वालों में देसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दिग्गज शामिल थे। जैसा कि मैंने कहा, राजनेता एक अलग ही दुनिया में रहते हैं।

ऐसा कोई व्यक्ति जिसे देश में कारोबार की समझ है। वह जानता है कि देश में कारोबार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना और लाखों रोजगार तैयार करना कितना मुश्किल है। जो कंपनियां बची रहीं और देश की विषाक्त राजनीतिक अर्थव्यवस्था में फली-फूलीं उन्हें रोज रिश्वत, निर्णय प्रक्रिया में देरी, तमाम तरह के कायदों और लाइसेंस, अदालती मुकदमों, राजस्व विभाग की मांग, पुरातन कानूनों आदि से निपटना पड़ा। उन्हें भाषण की जरूरत नहीं है। आखिर राजनेता, जिनमें से कुछ ने तो चुनाव भी नहीं जीता, जीवन में बहुत उपयोगी कुछ नहीं किया, रोजगार या संपत्ति नहीं पैदा की, उन्हें इन सफल उद्योगपतियों को यह भाषण देने में शर्म नहीं आती कि वे साहसी बनें और अपने संशय से बाहर निकलें?

वजह आसान है: एक बार सत्ता में आने के बाद वे हकीकत से दूर हो जाते हैं और तमाम असहज करने वाले तथ्यों को नकारात्मकता बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे कर रहे हैं वही सही है। वर्ष 2008 के बाद फंसे कर्ज में इजाफे के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का भी यही रुख था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था डांवाडोल है क्योंकि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार का कचरा साफ करना पड़ा। इसे सच मान लिया जाए तो क्या कोई प्रधानमंत्री से पूछेगा कि उन्होंने ऐसी गंदगी के जिम्मेदार व्यक्ति को भारत रत्न का खिताब क्यों दिया? हमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हम यह या ऐसे तमाम अन्य असहज करने वाले प्रश्न करें। जबकि नेता प्राय: एक दूसरे की बात दोहराते हुए यह बताते रहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक ही दिन यह अपील की कि कारोबारियों को घबराना नहीं चाहिए।

मुझे यह सब देखकर अचरज होता है कि आखिर रोजगार की कमी से जूझ रहे देश में रोजगार तैयार करने वाले सफल कारोबारी रोजगार नष्ट करने वाले राजनेताओं के समक्ष याचक की भूमिका में क्यों नजर आते हैं। उन्हें उनकी बेतुकी सलाह सुननी पड़ती है। पिछले दिनों एसोचैम की बैठक में प्रधानमंत्री पर्याप्त तालियां न बजने से नाखुश थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। इन सफल कारोबारियों ने इस अपमान पर हंसना शुरू किया और तालियां बजानी तेज कर दी। जब प्रधानमंत्री ने उनका और अपमान करते हुए आरोप लगाया कि वे विभिन्न मंत्रियों को फोन करके उनसे मदद का अनुरोध करते हैं तो वे खामोशी से सुनते रहे।

मैं समझता हूं कि इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार को पांच साल में एक बार ही बदला जा सकता है और इससे भी कुछ खास नतीजा निकलता नहीं दिखता। हमें कम से कम इस अंतहीन भाषणबाजी की अनदेखी करनी चाहिए और देशभक्ति, राष्ट्रवाद, उद्यमिता, स्वच्छता आदि को लेकर अंतहीन सवालों की झड़ी का शिकार बनने से इनकार करना चाहिए। इसलिए क्योंकि नेता, बाबू और राजनीतिक दल स्वयं को इन तमाम परीक्षणों से सुरक्षित रखते हैं।

भारतीय अदालतों में क्यों कारगर नहीं होगी कृत्रिम मेधा

अदालती आईना

एम जे एंटनी

कृत्रिम मेधा को भारत में कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुकदमा लड़ रहे लोगों को जीतने में मदद करने वाले ज्योतिषी वकीलों के चैंबरों के आसपास मंडराते रहते हैं।

अगर देश के सभी कानूनों को एक के बाद एक साथ जोड़ लिया जाए तो इससे एक अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 1,17369 शब्द हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 4,543 शब्द हैं। देश में 1,248 मुख्य कानून हैं। हालांकि केंद्रीय और राज्य कानूनों की कोई गिनती नहीं है। उच्चतम न्यायालय हर साल जो फैसले देता है, वे 16 खंडों में छपते हैं। इसे 24 उच्च न्यायालयों से गुणा कर दीजिए। फिर हर राज्य के लिए प्रक्रियागत नियम हैं। इन आंकड़ों को केवल कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) से ही संभाला जा सकता है। कृत्रिम मेधा विधि क्षेत्र में नई अवधारणा है।

अलबत्ता, भारतीय विधि व्यवस्था अब भी बुनियादी डिजिटल साक्षरता से जूझ रही है। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए शुरू की गई ई-फाइलिंग व्यवस्था को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पिछले तीन वर्षों में इसके माध्यम से केवल कुछ सौ याचिकाएं ही दायर की गई हैं। ऐसा वकील दिखना दुर्लभ है जो सामने लैपटॉप रखकर अदालत में अपनी दलील पेश करे। उच्चतम न्यायालय ने हाल में पास ही 12 एकड़ में फैली बहुमंजिला इमारतों में अपना विस्तार किया है। यह इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अभी कृत्रिम मेधा के लिए तैयार नहीं है। आम बजट में न्यायपालिका के लिए 0.2 फीसदी बजट रखा गया है, उसे देखते यही उम्मीद की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने हाल ही में घोषणा की थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर भी वह कृत्रिम मेधा की भूमिका को अहम मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रति सेकंड 10 लाख शब्द पढ़ सकता है और हजारों पन्नों वाले मामलों में सवालों का जवाब दे सकता है। हाल में अयोध्या मामले में ऐसा देखने को मिला था।

चूंकि न्यायपालिका की कृत्रिम मेधा अपनाने की रफ्तार बहुत धीमी है, इसलिए स्वाभाविक है कि विधि पेशेवरों की चाल भी धीमी है। डेटा क्रांति के लिए विधि कॉलेजों में बहुत कम तैयारी है। विधि विभाग पुराने पाठ्यक्रमों में उलझे हुए हैं और वे भविष्य में ऐसे वकील बनाने के लिए तैयार नहीं हैं जो कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर सकें। न्यायाधीशों की भी डिजिटल में रुचि नहीं है और वे अब भी पुराने दौर से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हालांकि कानून और प्रक्रियाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर धीरे-धीरे बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन अभी कुछ ही विधि फर्में उनका इस्तेमाल कर रही हैं। सामान्य वकील उनका बोझ वहन नहीं उठा सकते हैं और न ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वकील के कमरे में कानून की ढेरों किताबें रखी गई हैं तो मुवक्किल भी इससे प्रभावित होते हैं। वकील मौजूदा व्यवस्था में ज्यादा सहज महसूस करते हैं और इसे अपने कारोबार के लिए अच्छा मानते हैं।

कृत्रिम मेधा अभी मुख्य रूप से शोध के लिए उपयोगी है। अभी विधि फर्में में जूनियर वकील यह काम करते हैं। कृत्रिम मेधा के जरिये इस काम को बेहतर ढंग से किया जा सकता है। यह कंपनी जगह के मुवक्किलों को सलाह देने में मददगार है और इसके जरिये उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले पूरी प्रक्रिया से वाकिफ कराया जा सकता है। बार-बार होने वाले नियमित काम में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। सर्वेक्षणों के मुताबिक यह 70 फीसदी से अधिक सटीक होता है। विधि पेशेवरों को आशंका है कि एआई के आने के बाद उनका भी वही हाल हो सकता है जो भाप इंजन आने के बाद घोड़ों का हुआ था।

दूसरे मायनों में भी कृत्रिम मेधा का भविष्य वकीलों के लिए शुभ नहीं है। आशंका है कि एक बार शुरू होने के बाद यह किसी भी मामले के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। यह कानून, नजीर और न्यायिक सोच को बेहतर समझता है। इसमें केवल मानवीय कारक नहीं है जैसे न्यायाधीशों का रवैया और वकीलों के तर्क। अगर अदालत में कैमरे की अनुमति दी जाए तो कृत्रिम मेधा न्यायाधीश के भावों का बेहतर विश्लेषण कर सकता है।

अगर कृत्रिम मेधा का चलन आम हो गया तो मुवक्किल भी अपने मामलों की सफलता का अनुमान लगाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका पक्ष कमजोर है तो वे मध्यस्थता या निपटारे में जाना पसंद करेंगे। इससे विधि पेशेवरों का भारी नुकसान होगा। डॉक्टरों को अक्सर मरीजों के खास सवालों का सामना करना पड़ता है। गूगल ने अब लोगों को काफी समझदार बना दिया है। वकीलों को भी भविष्य में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अंत में कृत्रिम मेधा को भारत में कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुकदमा लड़ रहे लोगों को जीतने में मदद करने वाले ज्योतिषी वकीलों के चैंबरों के आसपास मंडराते रहते हैं। भृगु संहिता में मौजूदा और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी होती है। फिर कम से कम दो मंदिर ऐसे हैं जहां के देवताओं को मुकदमा लड़ रहे लोगों को जीत का आशीर्वाद देने में विशेषज्ञता हासिल है। इनमें से एक मंदिर हिमाचल में और दूसरा केरल में है।

कानाफूसी

झारखंड में साफ-सफाई

झारखंड में गठित नई सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तथा आईएएस अधिकारी सुनील कुमार बर्णवाल को उनके पद से हटा दिया। बर्णवाल वर्ष 2015 से इस पद पर थे और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता रघुवर दास का करीबी माना जाता था। सूत्रों ने कहा कि पिछले शासन में उनके कार्यों तथा कुछ दूसरी अटकलें इस निष्कासन का कारण रहे। हालांकि जल्द ही राज्य सरकार का बजट पेश किया जाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार केवल अहम पदों पर ही ध्यान दे रही है। ऐसी अटकलें भी हैं कि बर्णवाल ने चुनाव परिणाम घोषित होने से ठीक पहले ही केंद्र में किसी पद के लिए आवेदन कर दिया था। हालांकि बाद में इसके परिणाम के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल वह कार्मिक मामलों की समन्वय एजेंसी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से जुड़े हैं।

समानांतर समारोह

कांग्रेस पार्टी देशभर में अपना 135वां स्थापना दिवस (28 दिसंबर) मना रही है। पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई से निष्कासित कुछ नेताओं ने भी अलग से इस मौके पर जश्न मनाया लेकिन साथ ही पार्टी द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ आवाज भी उठाई। पिछले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक सिराज मेहंदी सहित राज्य के 10 वरिष्ठ नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एक तरफ उत्तर प्रदेश की 'आधिकारिक' कांग्रेस इकाई लखनऊ में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मेजबानी करने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर निष्कासित नेताओं ने दावा किया कि वे ही 'वास्तविक' कांग्रेस इकाई हैं। निष्कासित नेताओं ने कहा कि पार्टी की मौजूदा अनुशासनात्मक इकाई के पास उन्हें बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं था और इसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हैं।

आपका पक्ष

शांति से सुलझे राष्ट्रीय मसला

राष्ट्रीय महत्त्व के मसलों को हिंसा के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता है। बाहर से आए जो लाखों लोग दशकों से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्हें नागरिक या शरणार्थी घोषित करने का काम करना ही होगा। इस मामले में एक सीमा तक ही उदारता दिखाई जा सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह हर किसी को देश में रहने का अधिकार दे सके। विपक्ष असम की तर्ज पर पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा का विरोध कर रहा है लेकिन उसे यह समझना होगा कि हर देश को यह जानने का अधिकार है कि उसके यहां रह रहे लोगों में कौन उसके नागरिक हैं। अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने और दूसरे देशों के नागरिकों की पहचान करनी होगी। दूसरे देशों के नागरिकों की पहचान करते समय यह भी देखना होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

देश में नागरिकता संशोधन कानून का विपक्षी पर्टियां विरोध कर रही हैं

देश में विनिर्माण उद्योग की जरूरत

भारत में विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की बड़ी संख्या में जरूरत है। इस बात से सरकार या उद्योग जगत दोनों ही सहमत होंगे। इस बात पर गौर करना होगा कि क्या विनिर्माण उद्योग को दी जाने वाली प्रोत्साहन व सहूलियतें काफी हैं। बहरहाल उद्योगों के लिए पूंजी, भूमि और मशीनरी जितनी जरूरी श्रमशक्ति भी है। अच्छे प्रबंधक वे होते हैं जो विनिर्माण के लिए उत्तम श्रमशक्ति जुटाते हैं। देश से प्रतिभा पलायन रोकना जरूरी है। जो भारतीय युवा विकसित देशों में पहले से सेवारत हैं उन्हें घर वापसी के लिए मनाना जरूरी है। ऐसे युवा उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जो पहले से विकसित है।

हिम्मत जोशी, नागपुर

इस नववर्ष में सोच बदलने की जरूरत

नववर्ष में शुभकामनाएं देने के साथ हर किसी को अपने स्वार्थी, संकीर्ण और नकारात्मक सोच भी बदलनी चाहिए, तभी नववर्ष हर किसी के लिए मंगलमय और समाज, देश में नया परिवर्तन लेकर आएगा। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी न करें। नववर्ष पर परोपकार का संकल्प लिया जाए तो यह देश और समाज में एक नया और अच्छा बदलाव ला सकता है। देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने अंदर लोकसेवा की भावना का दीपक जलाए तो देश में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हर गरीब के भूखे पेट को भोजन मिल सकेगा। किसी गरीब को इलाज महंगा होने के कारण अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। भारत साल दर साल विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करता आ रहा है, साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी पैदा भी हुई हैं जो खुद इंसान और अन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। भारत में भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्याधियां बढ़ती जाएंगी। दुनिया में जो धर्म-संप्रदाय के नाम पर गलत काम हो रहे हैं वह इंसान के लिए उचित नहीं है। विश्वव्यापी समस्याओं का हल निकालने के लिए दुनिया के सभी नागरिकों, सत्ताधारियों को एकजुट होना चाहिए। अगर 2020 के लिए राजनेता और हर कोई देश के कल्याण के लिए संकल्प ले तो अवश्य ही देश में कुछ न कुछ अवश्य बदलाव हो सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

खाद्य परीक्षण किट की खरीद

खाद्य संरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने कहा कि वह देश भर में राज्य स्तर के फील्ड अधिकारियों के लिए खाद्यों का किफायती तरीके से त्वरित परीक्षण करने वाले किट या उपकरण को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नियामक 30 रैपिड फूड टेस्टिंग किट खरीदने की मंजूरी दे चुका है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्याधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा, 'अकेले भारत में इस तरह के किट - उपकरणों का 1,000 करोड़ रुपये का बाजार है।

उन्होंने कहा, 'रैपिड फूड टेस्टिंग किट और उपकरणों का व्यापक उपयोग वर्ष 2020 में भारत के लिए स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इससे बाजार में उपलब्ध भोजन के प्रति आम जनता का अधिक विश्वास कायम हो सकता है।'

उन्होंने एक बयान में कहा, 'अभी तक 30 उपकरणों पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो विभिन्न खाद्य उत्पादों जैसे दूध और खाद्य तेलों पर किए गए परीक्षणों के लिए त्वरित और मान्य परिणाम प्रदान कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'एफएसएसएआई 20 करोड़ रुपये खर्च करके त्वरित खाद्य परीक्षण किट और उपकरण खरीदेगा। ये राज्य सरकारों के माध्यम से फील्ड अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा।' *भाषा*

सोने-चांदी में आई खूब चमक

हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से आयात की लागत बढ़ी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 31 दिसंबर

नए साल में भी तेजी

- अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध से वैश्विक मंदी की चिंताओं और भूराजनीतिक तनाव और बढ़ने से भी सोने को सहारा मिला
- चांदी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी कीमतों में 21 फीसदी बढ़ोतरी हुई जो 2010 के बाद सबसे अधिक

सोने के दाम कम आपूर्ति और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद के कारण वर्ष 2019 में 23 फीसदी बढ़े हैं। यह पिछले आठ वर्षों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सुरक्षित संपत्तियां तलाश रहे निवेशकों से भी सोने को फायदा मिला है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से वैश्विक मंदी की चिंताओं और भूराजनीतिक तनाव और बढ़ने से भी सोने को सहारा मिला है। चांदी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी कीमतों में 21 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जो 2010 के बाद सबसे अधिक है।

हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से आयात की लागत बढ़ी है, जिससे ग्राहक अत्यधिक जरूरी होने पर ही सोने की खरीदारी कर रहे हैं। वर्ष 2019 की दूसरी छमाही में सोने की घरेलू मांग में अचानक गिरावट आने की अन्य वजह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट बने रहना और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हैं। आयात शुल्क में बढ़ोतरी ने चौंकाया है। इससे स्थिति और बिगड़ी है। सराफा डीलर शुल्क बढ़ोतरी से पहले आयातित सोना आयात लागत से कम दाम पर बेच रहे हैं। अवैध रूप से आयातित सोना कुछ समय भारी छूट पर बिका। उपभोक्ताओं ने भी मंदी के दौरान सोने को नकदी में बदला है। इसके नतीजतन जुलाई-अक्टूबर अवधि में मासिक आयात घटा।

ऐसा लगता है कि बहुप्रतीक्षित स्वर्ण नीति और हाजिर स्वर्ण एक्सचेंज सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं। इसके बावजूद सोना रखने वाले वाले लोग फायदे में हैं। उन्हें अन्य किसी संपत्ति वर्ग से अधिक फायदा मिला है। घरेलू सराफा बाजार का एक अन्य घटनाक्रम कुछ बड़े सराफा कारोबारियों का दिवालिया होना है, जिनके पास ग्राहक मासिक जमा योजना के तहत निवेश कर रहे थे। कुछ सराफों के ग्राहकों के करोड़ों रुपये लेकर छूमंतर होने के बाद अन्य सराफों की जमा योजनाओं पर भुनाने का दबाव बढ़ा है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि 2020 में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रतिफल करीब 6-7 फीसदी ही मिलने की उम्मीद है।

कॉमट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सुस्त आर्थिक कदमों के चलते यह रुझान 2020 में भी जारी रहेगा। इससे ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के दूसरे चरण को स्थगित किए जाने की संभावना का संकेत मिलता है।'

त्यागराजन का अनुमान है कि सोने के दाम विदेशी बाजार में बढ़कर 1,565 डॉलर और घरेलू बाजार में 41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक मांग बढ़ रही है, इसलिए चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

गोल्डमैन सैक्स ने हाल की अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि कमजोर वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों, भू-राजनीतिक तनाव की आशंकाओं और ब्रेक्जिट के असर के कारण सोना 2020 में 1,600 डॉलर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच तनाव घटने से आर्थिक सुधार और मंदी की चिंताएं कम होने की उम्मीद जगी है।

हालांकि मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में सहायक निदेशक किशोर नार्ने का बहुत अधिक सकारात्मक रुख नहीं है। वह कहते हैं, 'पहले हमने सोचा था कि सोने की कीमतों में 2020 की पहली छमाही में उठापटक होगी। लेकिन अब हमें एक बदलाव नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि दूसरी छमाही में उतार-चढ़ाव आएगा। सोने की कीमतें निकट भविष्य में सीमित दायरे में रहने के आसार हैं।'

सोना फिर 40 हजार के पार

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 31 दिसंबर

शीर्ष पर सोना

- मंगलवार को सोने के हाजिर कारोबार में कीमतों में 0.7 प्रतिशत की तेजी आई और यह सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं
- वर्ष 2019 में सोने की कीमतों में 24 प्रतिशत तथा चांदी की कीमतों में 22 प्रतिशत की उछाल

सोने की कीमतों में लगातार सात दिन की तेजी के साथ ही ये कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। मंगलवार को सोने के हाजिर कारोबार में कीमतों में 0.7 प्रतिशत की तेजी आई जिसके कारण ग्राहक फिलहाल नए ऑर्डर देने से दूरी बना रहे हैं।

पिछले 10 दिनों के दौरान मुंबई के प्रसिद्ध जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में तीन प्रतिशत तथा चांदी की कीमतों में छह प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोना कारोबार 39,083 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 46,665 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बंद हुआ। तीन प्रतिशत जीएसटी को जोड़ा जाए तो ग्राहकों को 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 40,000 रुपये से अधिक राशि खर्च करनी होगी।

सोने की कीमतों में घरेलू तथा विदेशी, दोनों बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है। भारत में ग्राहक मासिक जमा योजनाओं में निवेश पर प्रतिफल में कमी के चलते सोने में निवेश को अच्छे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। वर्ष 2019 में सोने की कीमतों में (रुपये में) 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि चांदी की कीमतों में 22 प्रतिशत की उछाल आई। हालांकि डॉलर कीमतों के अनुसार, वर्ष 2019 में सोने की कीमतों में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि चांदी की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई।

एबीयंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष अभिषेक बंसल कहते हैं, 'साल 2019 में भारत में सोने की कीमतों में तेजी आई है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में आई गिरावट, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के चलते पैदा हुई भूराजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता और आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना इसके कुछ प्रमुख कारण रहे। ईरान तथा सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में भूराजनैतिक तनाव को बढ़ा दिया, जिससे कच्चे तेल तथा सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है।'

4 सितंबर 2019 के बाद से (जब पिछली बार सोने से 39,031 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था) सोने से 2,000 रुपये तक का करेक्शन किया जिसने निवेशकों को नए ऑर्डर देने का अवसर दिया। इसके बाद से सोने की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही थीं।

आनंद राठी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकर्स के निदेशक (कमोडिटीज एवं करेंसी) नवीन माथुर कहते हैं, 'हमारा मानना है कि मजबूत मांग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 1,560 डॉलर प्रति औंस तक बढ़ जाएंगी। जिसका अर्थ होगा कि भारतीय बाजार में यह कीमतें 42,500-43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब होंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता, ब्रेक्जिट, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मध्य पूर्व में सैन्य तनाव के कारण वैश्विक निवेशकों के लिए सोना सुरक्षित निवेश बन गया है।'

हालांकि सोने की कीमतों में तेज वृद्धि से आभूषण दुकानों में खरीदारी में कमी देखी गई है और ग्राहक कीमतों में गिरावट आने का इंतजार कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 31	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,791.0	5.1	1,961.3	-1.4
Copper	6,183.5	8.0	6,500.4	6.6
Nickel	14,225.0	-19.0	14,850.1	-17.5
Lead	1,932.0	-7.3	2,199.5	4.6
Tin	16,975.0	5.7	17,862.1	1.3
Zinc	2,315.0	-2.6	2,563.7	-1.8
Gold ($/ounce)	1,521.1*	3.3	1,703.0	3.4
Silver ($/ounce)	18.0*	6.0	20.3	4.5
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	66.6*	11.2	68.0	11.6
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-6.6	2.2	-6.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	193.6	13.3	307.2	4.6
Maize	189.3*	5.6	331.7	9.9
Sugar	361.2*	4.9	487.7	-1.2
Palm oil	775.5	50.6	1,215.3	43.5
Rubber	1,635.8*	13.0	1,835.2	4.5
Coffee Robusta	1,347.0*	2.0	1,863.3	-5.7
Cotton	1,535.5	16.6	1,593.0	-3.4

* As on Dec 31, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months

* As on Dec 30, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	47.4	16720
Oil and Oilseeds	294.7	71549
Spices	0.5	15
Metal(Dec 30)		
Metal- non ferrous	3171.8	45447
Metal- precious	9155.8	417
Oil and gas(Dec 30)		
Gas	2914.3	46899
Oil	12092.4	2789

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	212.6	115982
Grains	240.7	104325
Oil and Oilseeds	1070.2	566145
Others	254.1	71960
Pulses	82.3	40420
Spices	85.7	29793

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3791.4	7.5
Natural Gas (Jan 28)	157.9	0.6
Cotton (Dec 31)	19330.0	0.3
Aluminium Mini (Dec 31)	137.9	0.3
Nickel (Dec 31)	1078.6	0.2
Losers (* % Change)		
Mentha Oil (Dec 31)	1280.0	-1.5
Kapas (Apr 30)	1121.0	-1.2
Lead Mini (Dec 31)	150.0	-1.0
Crude Palm Oil (Dec 31)	803.3	-0.6
Gold Mini (Jan 03)	38823.0	-0.4
Aluminium (Dec 31)	136.6	-0.4
Crude Oil (Jan 17)	4401.0	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6848.0	3.8
Bajra (Jan 20)	2041.0	0.5
Chana-Bikaner (Jan 20)	4495.0	0.0
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2139.0	-2.6
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	939.2	-1.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16245.0	-1.2
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4658.0	-1.2
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4190.0	-1.2
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1123.0	-1.1
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7748.0	-1.0
Guar Seed 10 (Jan 20)	4230.0	-0.9
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6562.0	-0.8

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3791.4	4.7
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19330.0	2.3
Nickel Mumbai (Dec 31)	1078.6	2.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46870.0	0.6
Silver Ahm (Mar 05)	46855.0	0.6
Discount over spot price(In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1280.0	-10.2
Lead Min Mumbai (Dec 31)	150.0	-3.5
Aluminium Mum (Dec 31)	136.6	-2.8
Lead Mum (Dec 31)	151.1	-2.8
Copper Mum (Dec 31)	441.6	-2.6
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	178.9	-2.5
Alumini-Mumbai (Dec 31)	137.9	-1.9

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6562.0	5.0
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3236.0	2.7
Maize-Sangli (Jan 20)	2046.0	2.5
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	18890.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Soy Bean Indore (Jan 20)	4436.0	-3.5
Coriander-Kota (Jan 20)	6848.0	-3.3
Moong-Merta City (Jan 20)	7396.0	-2.2
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	826.9	-1.8
Barley Jaipur (Jan 20)	2139.0	-1.4
Jeera Unjha (Jan 20)	16245.0	-1.1
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7748.0	-0.6

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	104 (104)
Aluminium ingots /kg	140 (140)
Brass sheet cutting /kg	328 (328)
Brass utensil scraps/kg	310 (310)
Copper heavy scrap /kg	431 (432)
Copper utensil scraps/kg	403 (403)
Copper wire bar /kg	464 (463)
Lead ingots /kg	157 (157)
Nickel Cathodes /kg	1060 (1060)
Tin slabs /kg	1275 (1270)
Zinc slabs /kg	183 (184)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10320 (10320)
DCH - 32 /Qtl	11248 (11276)
Jaydhar /Qtl	9983 (9983)
Shankar- 6 /Qtl	11051 (11051)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	893 (898)
Castor Comm /10kg	883 (888)
Ricebran oil/10kg	- (820)
Groundnut oil /10kg	1180 (1170)
Linseed oil /10kg	- (1000)
Karanji /10kg	- (800)
Palm oil /10kg	870 (848)
Sunflower exp ref /10kg	935 (920)
Sunflower oil exp /10kg	895 (890)
Soyabean ref / 10kg	935 (925)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3370-3592 (3370-3592)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	61.68 (61.68)
Brent Crude (UK)	67.17 (67.13)
Brent Crude (WTI)	61.68 (61.68)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.18 (2.19)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	278.69 (277.36)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39083 (38822)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39240 (38978)
Silver.999/ kg	46665 (46130)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18827.80	18843.75
Alumini-Mumbai (M)	1 K	141.30	140.50
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2050.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2050.00	2041.95
Barley Jaipur (N)	1 Q	2162.85	2170.20
Brass-Jamnagar (M)	1 K	324.90	319.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4354.30	4301.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4262.50	4250.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4435.80	4413.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4650.00	4650.00
Chana-Akola (N)	X	4506.25	4475.00
Coriander-Gondal (N)	X	6613.00	6753.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6800.00	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7002.70	7084.35
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2222.50	2200.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2223.95	2173.15
Cotton-Kadi (N)	1 B	18787.95	18835.75
CPO-Kandla (M)	10 K	807.20	817.30
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	845.65	842
Gold Ahm (M)	10 G	38806.00	39076.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31170.00	31386.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3895.00	3920.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7869.15	7797.50
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4189.60	4143.25
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1261.70	1278.35
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16369.05	16425.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1051.60	1050.85
Kapas-Rajkot (N)	X	1060.35	1056.35
Lead Mum (M)	1 K	154.15	155.40
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2051.90	2034.40
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2461.35	2460.10
Maize-Erode (N)	X	2112.20	2095.55
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2255.00
Maize-Sangli (N)	X	2000.90	1996.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7461.50	7560.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4849.00	4887.65
Nickel Mumbai (M)	1 K	1059.30	1055.50
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3225.00	3150.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	35000.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2103.05	2110.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	860.00	867.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	944.80	941.60
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	927.60	936.25
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	957.50	960.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46049.00	46595.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4568.00	4595.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4452.50	4507.15
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4585.40	4595.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4534.00	4542.00
Soymeal Indore (N)	1 T	37588.00	37060.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3305.00	3305.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3428.55	3428.55
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3264.50	3261.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3504.75	3504.75
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3326.25	3335.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3102.50	3108.35
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6210.00	6250.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2333.75	2340.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2185.00	2217.50
Wheat New Indore (N)	1 Q	2275.00	2275.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2160.00	2160.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2275.00	2290.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	6100.00	5900.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	183.50	183.45

* as on Dec 30, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity Open, High Low Close Qty Trds OI

DAY SESSION

दिवस सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Cotton

Cotton MCX(1 B)
Dec 31 19290, 19840, 19220, 19330 ....68 10 863
Jan 31 19530, 19540, 19440, 19470 ....3771 498 13244
Feb 28 19720, 19770, 19690, 19750 ....102 22 1616

CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)
Jan 20 2198, 2208, 2134, 2139 ....45580 3260 53210
Feb 20 2219, 2227, 2155, 2163 ....32880 2513 51490
Mar 20 2240, 2242, 2181, 2188 ....2970 249 5840
Apr 20 2269, 2269, 2217, 2226 ....860 52 1040

Kapas MCX(20 K)
Apr 30 1136, 1136, 1117, 1121 ....396 89 900

Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)
Apr 30 1137.5, 1138, 1118.5, 1123 ....1471 787 4402

Grains

Bajra NCDEX(1 Qtl)
Jan 20 2045, 2045, 2041, 2041 ....20 2 90

Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)
Jan 20 4270, 4272, 4202, 4230 ....33050 3671 55290
Feb 20 4314, 4318, 4250, 4276 ....23260 2691 46725
Mar 20 4342, 4344, 4306, 4336 ....140 27 270

Oil and Oilseeds

CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)
Jan 20 4252, 4260, 4118, 4190 ....6105 637 22865
Feb 20 4288, 4288, 4144, 4212 ....4665 472 13205
Mar 20 4202, 4222, 4170, 4190 ....655 107 6720
Apr 20 4216, 4220, 4172, 4190 ....425 57 1765

Crude Palm Oil MCX(10 K)
Dec 31 806.7, 806.7, 803.1, 803.3 ....3330 243 12450
Jan 31 816.6, 817, 797.7, 799.1 ....25300 1825 43970
Feb 28 819.2, 821, 798, 798.2 ....6010 468 14150
Mar 31 800.9, 801.4, 790, 796 ....60 5 720

Name Exchange (Units)

Maturity Open, High Low Close Qty Trds OI

Mentha Oil MCX(1 K)
Dec 31 1280, 1280, 1280, 1280 ....0.36 1 8.64
Jan 31 1308.6, 1313, 1302, 1305.5 ....104.4 267 242.64
Feb 28 1317, 1321.9, 1313.1, 1313.7 ....12.6 31 7.2

Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)
Jan 20 4717, 4744, 4650, 4658 ....16600 1435 17250
Feb 20 4739, 4755, 4646, 4667 ....12970 1029 7800
Apr 20 4618, 4635, 4560, 4564 ....3930 311 10500
May 20 4630, 4630, 4615, 4615 ....30 3 600

Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)
Jan 20 952.8, 954, 937.2, 939.2 ....22025 2603 40280
Feb 20 949, 949.4, 935, 936.2 ....17470 1947 51665
Mar 20 937, 941, 926.2, 927.6 ....3085 406 23030
Apr 20 925.6, 930.4, 919, 923.8 ....740 103 1495
May 20 921.6, 921.6, 915, 915 ....35 7 30

Soyabean Indore NCDEX(1 Q)
Jan 20 4490, 4506, 4420, 4436 ....46405 5124 108400
Feb 20 4488, 4526, 4442, 4458 ....40105 4716 167685
Mar 20 4508, 4544, 4460, 4484 ....13455 1502 81195
Apr 20 4530, 4566, 4496, 4512 ....1460 163 11075
May 20 4572, 4572, 4546, 4546 ....55 8 585

Others

GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)
Jan 20 7852, 7852, 7715, 7748 ....17120 1626 23425
Feb 20 7940, 7945, 7820, 7839 ....14785 1358 47635
Mar 20 8000, 8000, 7939, 7941 ....605 75 900

Pulses

Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)
Jan 20 4475, 4518, 4465, 4495 ....14610 1089 29450
Mar 20 4435, 4465, 4425, 4438 ....3680 334 10450
Apr 20 4440, 4450, 4430, 4430 ....70 7 410

Spices

Cardamom MCX(1 K)
Jan 15 3759.5, 3796, 3759.5, 3791.4 ....0.8 8 7
Feb 14 3669.2, 3704.8, 3669.2, 3697.5 ....0.6 6 7

Coriander-Kota NCDEX(1 Q)
Jan 20 6618, 6860, 6590, 6848 ....5080 417 8980
Apr 20 7230, 7377, 7230, 7355 ....2070 199 7030
May 20 7425, 7437, 7365, 7407 ....150 15 70

Jeera Unjha NCDEX(1 Q)
Jan 20 16460, 16530, 16160, 16245 ....855 260 1785
Mar 20 15980, 15980, 15820, 15850 ....255 82 909
Apr 20 15630, 15650, 15500, 15575 ....63 18 264

Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)
Mar 20 6610, 6672, 6502, 6562 ....2080 357 6420
Apr 20 6476, 6550, 6420, 6474 ....325 58 4285
May 20 6574, 6574, 6500, 6500 ....20 4 50

धातु

Metal- non ferrous

Aluminium MCX(1 K)
Dec 31 136.25, 137.65, 135.5, 137.25 ....180 9 415

Aluminium Mini MCX(1 K)
Dec 31 138.5, 138.5, 137, 137.45 ....126 21 118
Jan 31 137.7, 138, 137.4, 137.85 ....2766 1665 5528

Name Exchange (Units)

Maturity Open, High Low Close Qty Trds OI

Feb 28 138.05, 138.25, 137.85, 138 ....169 139 305

Copper MCX(1 K)
Dec 31 440.8, 440.8, 438.9, 439.3 ....240 90 335
Jan 31 444.1, 444.2, 441.55, 442.85 ....6947.5 2314 12602.5
Feb 28 447.55, 447.85, 446.15, 446.6 ....187.5 75 565
Mar 31 446, 450, 446, 448 ....10 4 -

Lead MCX(1 K)
Dec 31 150, 150, 149.3, 149.75 ....20 4 120

Lead Mini MCX(1 K)
Dec 31 150, 150, 149.9, 149.95 ....20 5 20
Jan 31 152.4, 152.4, 151.65, 152.15 ....4786 3021 5396

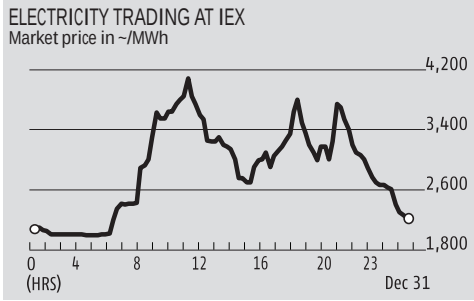

Feb 28 152.75, 152.8, 152.1, 152.65 ....58 58 133

Nickel MCX(1 K)
Dec 31 1077.1, 1086.2, 1076.6, 1082.6 ....28.5 15 3
Jan 31 1045.6, 1050.6, 1042.2, 1044.2 ....7648.5 4475 2857.5
Feb 28 1044.5, 1049.3, 1041.2, 1042.4 ....75 50 45

Zinc MCX(1 K)
Dec 31 180.9, 180.9, 179.1, 179.75 ....15 3 170

Zinc Mini MCX(1 K)
Dec 31 178.35, 179.1, 178.35, 178.55 ....150 141 236
Jan 31 180, 180.2, 179.45, 179.75 ....10270 5700 20583
Feb 28 180.3, 180.5, 180.05, 180.35 ....591 410 2364

Metal- precious

Gold MCX(10 G)
Feb 05 39053, 39270, 39053, 39192 ....4.62 3815 15.93
Apr 03 39241, 39334, 39232, 39289 ....0.65 467 6.03

Gold Guinea MCX(8 G)
Dec 31 31199, 31700, 31199, 31375 ....0 14 0
Jan 31 31113, 31219, 31113, 31189 ....0 176 0.01
Feb 28 31070, 31244, 31070, 31216 ....0 18 0
Mar 31 31900, 31900, 31300, 31686 ....0 7 0

Gold Mini MCX(10 G)
Jan 03 39019, 39099, 38936, 39063 ....0.04 250 0.07
Feb 05 39000, 39190, 39000, 39151 ....0.53 4429 1.18
Mar 05 39125, 39225, 39122, 39193 ....0.04 349 0.1

Gold Petal MCX(1 Gm)
Dec 31 3908, 3940, 3900, 3924 ....0 25 0
Jan 31 3908, 3915, 3905, 3911 ....0 862 0.01
Feb 28 3895, 3911, 3895, 3909 ....0 143 0
Mar 31 3900, 3900, 3900, 3900 ....0 1 0

Silver MCX(1 K)
Mar 05 47245, 47323, 47112, 47

सौर ऊर्जा पंप से बदली किसानों की जिंदगी

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने राजस्थान और हरियाणा के उन चार जिलों का जायजा लिया जहां पानी की कमी है और इन जगहों पर सौर ऊर्जा से संचालित पंपों से जिंदगी में कैसे बदलाव आ रहा है। जायजा ले रही हैं **ज्योति मुकुल**

जगदीश प्रसाद यादव के लिए सूरज कभी अस्त नहीं होता। वह तीन भाइयों में अकेले ऐसे शख्स हैं जो खेती से जुड़े हैं और अपनी 4.5 हेक्टेयर जमीन पर साल भर कड़ी मेहनत करते हैं। खेती के नए तरीके के बारे में जानने और सीखने को लेकर उनमें काफी दिलचस्पी है। वह किसानों की बैठक में नियमित तौर पर हिस्सा लेते हैं। बेहद उत्साह के साथ वह कहते हैं, 'मैं हम सबकी सेल्फी लेता हूं। इस फोटो को मैं अपने किसानों के व्हाट्सऐप ग्रुप में डालूंगा और आपके यहां आने के बारे में सबको बताऊंगा।' वह अपने पॉलिहाउस से बाहर निकलते हैं जहां वह संकर खीरा उगाते हैं। इस संकर खीरे को शहर के वेंडर 'चाइनीज खीरा' कहते हैं। पॉलिहाउस पॉलिथीन से बना एक घर होता है जिसका इस्तेमाल खास किस्म के कृषि उत्पादों की खेती के लिए किया जाता है। 0.4 हेक्टेयर के इस पॉलिहाउस में सलाद की दो सब्जियों की खेती से उन्हें 16 लाख रुपये मिले हैं।

राजस्थान में पॉलिहाउस बनाने के लिए 70 फीसदी सब्सिडी दी जाती है लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसके लिए किसानों को अपने खेत में छोटे पैमाने वाली सिंचाई का तरीका अपनाना होगा। अगर खेती की जमीन 0.5 हेक्टेयर से अधिक है तब तालाब तैयार कर बारिश का पानी संग्रह कर सिंचाई करने के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है और यह फव्वारा, छिड़काव वाली सिंचाई और पलवार (सूखी जमीन को नम बनाना) से अलग होती है। सब्सिडी का फायदा पाने के लिए किसानों को सूक्ष्म स्तर की सिंचाई करना जरूरी है। जयपुर जिले की चौमू तहसील के इटावा भोपजी गांव के यादव एक मॉडल किसान हैं और उन्होंने इस साल खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ लिया है। उनका एक सुझाव भी है, 'सरकार को यह अनुमति देनी चाहिए कि सौर जल सिंचाई पंप से मिलने वाले थ्री फेज बिजली कनेक्शन को सिंगल फेज में बदला जाए ताकि घर के लिए भी बिजली मिल सके। इससे मेरे घर के बिजली बिल में भी कमी आएगी।'

सूरज, पानी और मिट्टी
भाग-1

हरियाणा में राम प्रसाद कई चुनौतियों की बात करते हैं जबकि जयपुर के किसान जगदीश योजनाओं का लाभ ले रहे हैं

राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले 44,242 सिंचाई पंप हैं जबकि हरियाणा में ऐसे 3,542 पंप हैं। दोनों ही राज्यों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है और इन राज्यों में ऐसे पंप के लिए सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन इस सब्सिडी का लाभ पाने के लिए सिंचाई के लिए इन किसानों के पास ग्रिड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि किसान अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी इस तरह के सोलर कनेक्शन ले लेते हैं। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के झुंझुनूं की सीमा से लगता है और यहां के एक गांव देरोली अहीर के 81 वर्षीय राम प्रसाद के सामने कुछ बुनियादी चुनौतियां हैं। उन्हें अपने खेत में लगे सोलर प्लेट के नीचे ही सोना होता है क्योंकि यहां चोरी की समस्या ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के ज्यादातर किसानों के घर खेत में हैं और वहीं सौर पंप भी लगा है जबकि महेंद्रगढ़ में खेत घरों से दूर हैं। ठंड की वजह से कांपती आवाज में प्रसाद कहते हैं, 'क्या आप बिजली विभाग से कह सकती हैं कि हमें इन सोलर प्लेट को छत पर लगाने की अनुमति मिले। इससे हमें आवारा पशुओं और चोरों की चिंता से राहत मिलेगी।' हरियाणा सरकार के दिशानिर्देश के तहत ऑफ ग्रिड सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम, किसानों, गौशाला, पानी का इस्तेमाल करने वाले संगठनों और समुदाय या क्लस्टर आधारित सिंचाई व्यवस्था के लिए 75 फीसदी सब्सिडी (राज्य और केंद्रीय आवंटन) के साथ मिलती है।

आंकड़ों में कुसुम

अहम हिस्से

526 मेगावॉट
माइक्रो ग्रिड लगाना

173,700
सोलर वॉटर पंप

100,000
ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की कवायद

कैसी है योजना

केंद्र जल्द ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) शुरू करेगा जिसके तहत उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान और हरियाणा में ज्यादातर वितरण कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली इस्तेमाल में थ्री फेज और सिंगल फेज कनेक्शन में अंतर करती हैं। राजस्थान सरकार में प्रधान सचिव (बिजली) कुंजी लाल मीणा कहते हैं, 'थ्री फेज कनेक्शन के लिए हम एक दिन में छह या नौ घंटे तक की बिजली देते हैं। सिंगल फेज के लिए हम पूरे दिन बिजली देने की कोशिश करते हैं। इससे फीडर को अलग करने की लागत बचती है।' राज्य में उदय योजना के तहत 1,300 फीडर का लक्ष्य है। इस योजना का करीब 90 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

कुसुम योजना में तीन अहम बिंदु हैं, पहला, विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा संयंत्र, दूसरा, सौर कृषि पानी पंप और तीसरा, ग्रिड से जुड़े खेती वाले पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। पहली योजना के मुताबिक 10,000 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करना, दूसरी योजना के मुताबिक 17.5 लाख सौर कृषि पंप और तीसरी के मुताबिक 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। दूसरी योजना पर पूरा अमल किया जाएगा और इसके लिए केंद्र 19,036 करोड़ रुपये का सहयोग दे रही है जबकि पहली और तीसरी योजना को पहले प्रायोगिक आधार पर चलाया जाएगा जिसके बाद केंद्र का कुल सहयोग 15,385.5 करोड़ रुपये तक का होगा। इन तीनों योजनाओं के जरिये वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावॉट का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यों का स्थिति

पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने पहली योजना के लिए डेवलपरों से मांग का आवेदन करना शुरू किया है। राजस्थान 3.14 रुपये प्रति यूनिट (किलोवॉट/घंटा) की दर को अंतिम स्वरूप दे रही है जिस दर पर राज्य की वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) विकेंद्रीकृत इकाइयों की तरफ से बिजली खरीदेंगी जबकि तीसरी योजना के तहत दर 3.44 रुपये हो सकती है जिसके सौर पंप से अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियां खरीदेंगी। हरियाणा एक अलग व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। यमुनानगर और करनाल जिले में दो पावर फीडर लगाए गए हैं।

राज्य ने सौर संचालित पंप लगाने के लिए 225 करोड़ रुपये का निवेश किया है जिसका मालिकाना हक शुरुआती पांच सालों के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण या राज्य की वितरण कंपनियों के पास रहेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2019 में मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके बावजूद कुसुम की शुरुआत में देरी हुई। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक बड़ी निविदा के जरिये हाल में पांच राष्ट्रीय जोन के लिए पंपसेट आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची को अंतिम रूप दिया है। एक पखवाड़े के भीतर हरियाणा से इस योजना की औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। ऐसे में यादव और प्रसाद जैसे किसान जो बेहतर पैदावार के लिए अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर संभावनाएं बनेंगी।

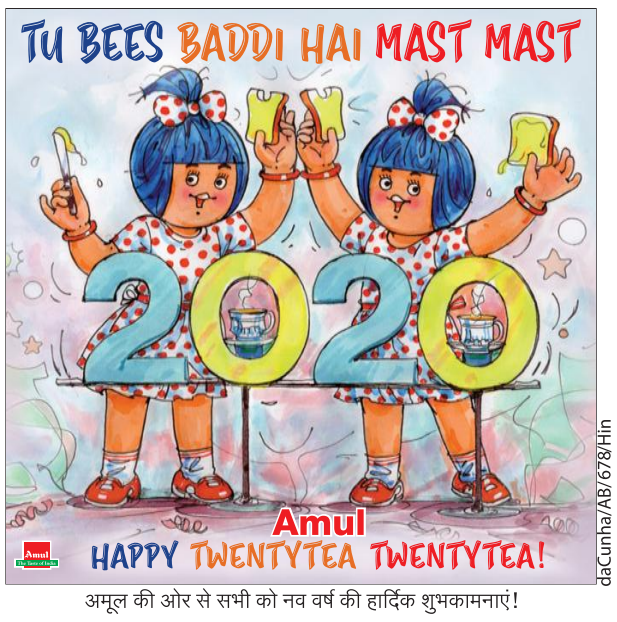

अमूल की ओर से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

नागरिकता प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में हुआ प्रस्ताव पारित

बीएस संवाददाता/एजेंसियां

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, केरल विधानसभा नागरिकता पर कानून पारित नहीं करा सकती

केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव मंगलवार को एक दिन के विशेष सत्र में पारित हो गया। इस तरह वाम दल द्वारा शासित यह पहला राज्य है जिसने इस विवादास्पद कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विचार कर रहा है ताकि अगर कोई राज्य इसका विरोध भी करे तो इस प्रक्रिया पर असर न पड़े।

गृह मंत्रालय जिलाधिकारी के जरिये नागरिकता का आवेदन देने की मौजूदा प्रक्रिया को खत्म करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए एक नया अधिकारी अधिकृत किया जाएगा। तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि इन राज्यों की विधानसभाओं में भी केरल की तरह ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर नागरिकता संशोधन कानून को खत्म करने की मांग की जाए। कई गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है कि वे नागरिकता संशोधन कानून पर अमल नहीं करेंगे लेकिन इन राज्यों की विधानसभाओं ने अब तक किसी औपचारिक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति नहीं दी है।

केरल का विरोध

केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को राज्य में सत्तारुढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ), माकपा और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने समर्थन किया जबकि 140 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एकमात्र विधायक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव में कहा गया, 'संसद के दोनों सदनों में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक से समाज के कई वर्गों में चिंता की स्थिति बनी हुई है। नया कानून संविधान के भाग 3 में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी अधिकार के खिलाफ है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय करना ही देश के संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया है।' विधानसभा में ओ राजगोपाल एकमात्र भाजपा विधायक थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि दूसरे दल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी यह घोषणा की है कि सरकार अवैध प्रवासियों के लिए कोई बंदीगृह बनाने की योजना नहीं बना रही है।

राज्य विधानसभाओं को अधिकार नहीं

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां सिर्फ संसद के पास है और केरल विधानसभा सहित किसी राज्य विधानसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। केरल विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद उनका बयान आया है। इस संशोधित कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करने के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, 'यह कानून भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस कारण यह नागरिकता ना तो सृजित करता है और न ही छीनता है।' उन्होंने यह याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्रमशः युगांडा के अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता मुहैया करायी थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर उन्होंने कहा कि यह भारत के 'सामान्य निवासियों' के बारे में सूचनाओं का व्यापक संग्रह है और इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।

देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (बाएं) के साथ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत (फोटोः पीटीआई)

नए सेना प्रमुख और सीडीएस ने दिया पाकिस्तान को कड़ा संदेश

देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और भारत के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (सीडीएस)नियुक्त किए गए जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोकता है तो इस स्थिति में भारत के पास आतंक के स्रोत पर हमला करने का अधिकार है और देश सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बखूबी तैयार है।

थल सेना के 28वें प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद एक साक्षात्कार में नरवणे ने कहा कि प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ 'दृढ़ संकल्पित दंडात्मक जवाब' की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की राज्य प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान हटाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गयी हैं और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में हालात सुधरे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवादियों के सफाए और आतंकी नेटवर्क की तबाही के कारण पाकिस्तानी सेना के छद्म युद्ध की मंशा को झटका लगा है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के उकसावे या उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए उनके पास कई विकल्प हैं। चीन के साथ लगी 3500 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर जनरल नरवणे ने कहा, 'हमने पश्चिमी सीमा से उत्तरी सीमा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम उत्तरी सीमा के पास क्षमता निर्माण में सुधार करना जारी रखेंगे।' चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'हम समूचे सैन्य तंत्र में जो महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहते हैंए सीडीएस निस्संदेह उन बदलावों की राह तैयार करेंगे।' सेना प्रमुख ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान किसी भी क्षण किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सुधार से दक्षता और संचालन तैयारी में सुधार होगा।

सेना है तैयार

जनरल बिपिन रावत ने भी कहा कि पाकिस्तान-चीन से लगी सीमा पर पैदा होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना बखूबी तैयार है। जनरल रावत ने मंगलवार को थल सेना प्रमुख पद से सेवानिवृत्त होने से कुछ घंटे पहले इसका जिक्र किया कि थल सेना का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण सेना प्रमुख के उनके कार्यकाल के दौरान बड़ी उपलब्धियों में शामिल रही। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को 27 वें थल सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला था और शानदार करियर के बाद इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। *एजेंसियां*

स्वच्छ शहर: इंदौर का दबदबा कायम, भोपाल पिछड़ा

लगातार तीन बार देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का खिताब हासिल करने वाले इंदौर ने 'स्वच्छता सर्वेक्षण 2020' शुरू होने से पहले सफाई के इस सालाना मुकाबले में बढ़त बना ली है। आगामी 4 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस सर्वेक्षण की दो आरंभिक रैंकिंग में मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर देश भर में अव्वल रहा है। इन नतीजों के बाद इंदौर की महापौर ने शहरवासियों को बधाई दी है। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 'अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर' के ये तिमाही आधारित नतीजे मंगलवार को नई दिल्ली में घोषित किये।

इन नतीजों से उत्साहित इंदौर की महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ ने ट्विटर पर शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा, 'अब मुख्य परीक्षा की घड़ी आने वाली है। आगामी चार से 31 जनवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चलेगा। हमें इस सर्वेक्षण में भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है।'

'स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020' की तिमाही रैंकिंग से पता चलता है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल साफ-सफाई की दौड़ में पिछड़ गयी है। इस लीग की पहली तिमाही 'अप्रैल से जून' रैंकिंग में भोपाल 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर था। लेकिन इस श्रेणी के शहरों की दूसरी तिमाही रैंकिग 'जुलाई से सितंबर' में भोपाल तीन पायदान नीचे खिसककर पांचवें स्थान पर आ गया। 'स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020' की पहली और दूसरी तिमाही रैंकिंग में एक से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्यप्रदेश का खरगोन शीर्ष तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस लीग के तीसरे चरण, 'अक्टूबर से दिसंबर' के नतीजे आने बाकी हैं। 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020' में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिये प्रतिभागी शहरों को इसकी तीनों लीगों में भी उम्दा प्रदर्शन करना जरूरी है जिनके जरिये साफ-सफाई की स्थिति को अलग-अलग पैमानों पर लगातार आंका जाता है।

लगातार तीसरी बार इंदौर को मिला यह तमगा

एजेंसियां

पृष्ठ 1 का शेष

नए साल में नियुक्तियों पर जोर

सीईओ ने कहा कि हाल के महीनों में कर अधिकारियों ने दिसंबर तिमाही में कई बार कर की मांग की है और कुल मांग का 20 प्रतिशत हिस्से का भुगतान उन्हें तत्काल करने के लिए कह रहे हैं। एक सीईओ ने कहा, 'कर विभाग को लगता है कि 20 प्रतिशत भुगतान मिलने से उसे अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।'

अर्थव्यवस्था को गति देने के सरकार के उपायों के बारे में पूछे जाने पर करीब 58 प्रतिशत सीईओ ने कहा कि वे इन कदमों से खुश जरूर हैं, लेकिन अतिरिक्त पहल किए जाने की दरकार है। गोयनका ने कहा, 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना, रेलवे सहित बुनियादी क्षेत्र की मजबूती पर जोर, कंपनियों के लिए करों में कमी और ब्याज दरों में कमी आदि कदम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए हैं।' हालांकि 40 प्रतिशत सीईओ सरकार के कदम से नाखुश हैं। सीईओ ने कहा, 'सरकार द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं। देश में कारोबारी माहौल बेहतर करने की तत्काल जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जीएसटी में कुछ त्रुटियां थीं, जिस वजह से उद्योग जगत के लिए हालात और बिगड़ते चले गए।'

करीब 38 प्रतिशत सीईओ को लग रहा है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2020 तक 46,000 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। केवल 16 प्रतिशत सीईओ को ही सेंसेक्स 46,000 पार करता दिखाई दे रहा है। प्रतिकूल आर्थिक हालात के बावजूद ज्यादातर सीईओ ने कहा कि वे नए साल में अधिक नियुक्तियां करने पर विचार कर रहे हैं। करीब 66 प्रतिशत ने कहा कि वे नए साल में अधिक निवेश करेंगे। करीब तीन चौथाई सीईओ ने कहा कि नए साल में भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ती महंगाई के मद्देनजर दरों में कटौती से परहेज करेगा।